● वर्ष-3
● अंक-93
रायपुर, रविवार
26 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कैरियर चुनने से पहले जरूरी होती....

बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस में चिंतन, सनातन धर्म की छवि खराब करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे

घोषणापत्र में हिंदूवाद नहीं, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करने पर जोर

बैंकॉक। यदि आप हिंदूवाद जिसे अंग्रेजी में हिंदुइज्म कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह गलत है क्योंकि इसका अर्थ सनातन धर्म की सही छवि नहीं प्रकट करता लेकिन यदि आप हिंदू और हिंदुत्व शब्द का उपयोग करते हैं तो यह एकदम सही है। आजकल देखने को मिल रहा है कि सनातन धर्म की छवि खराब करने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और पौराणिक ग्रंथों में लिखी गयी बातें तथा इतिहास के घटनाक्रमों को अलग दृष्टि से प्रस्तुत कर हिंदू धर्म पर हमला किया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर चिंतन करने के लिए इस समय थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है।

विश्व हिंदू कांग्रेस का घोषणापत्र

इस कार्यक्रम में देश-दुनिया के तमाम हिंदू विचारक और बुद्धिजीवी अपने विचार रख रहे हैं। विश्व हिंदू कांग्रेस में जो बड़े फैसले लिये गये हैं उसके तहत सनातन धर्म को संदर्भित करने के लिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म शब्दों को अपनाया गया है। इसके साथ

ही, हिंदूवाद (हिंदुइज्म) शब्द त्यागने का तर्क देते हुए कहा गया है कि यह शब्द दमन और भेदभाव को दर्शाता है। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस (डब्ल्यूएचसी) ने एक घोषणापत्र को अंगीकार किया जिसमें कहा गया है कि हिंदुत्व शब्द अधिक सटीक है क्योंकि इसमें हिंदू शब्द के सभी अर्थ शामिल हैं। विश्व हिंदू कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया, ''हिंदू धर्म शब्द में पहला शब्द अर्थात् हिंदू एक असीमित शब्द है। यह उन सभी का प्रतीक है जो सनातन या शाश्वत है। और फिर धर्म है, जिसका अर्थ है वह, जो कायम रखता है।'' घोषणापत्र में कहा गया है कि इसके विपरीत, हिंदूवाद (हिंदुइज्म) पूरी तरह से अलग है क्योंकि इसमें ''इज्म'' जुड़ा हुआ है, जो एक दमनकारी और भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण या विश्वास के रूप में परिभाषित शब्द है। घोषणापत्र में कहा गया है, ''इसी वजह से हमारे कई बुजुर्गों ने हिंदूवाद की तुलना में हिंदुत्व शब्द को प्राथमिकता दी क्योंकि हिंदुत्व अधिक सटीक शब्द है, इसमें हिंदू शब्द के सभी अर्थ शामिल हैं। हम उनसे सहमत हैं और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए।'' घोषणापत्र में कहा गया कि हिंदुत्व कोई जटिल शब्द नहीं है और इसका सीधा सा मतलब हिंदू से संबंधित है। घोषणापत्र में कहा गया, ''अन्य लोगों ने विकल्प के तौर पर ''सनातन धर्म'' का उपयोग किया है, जिसे संक्षिप्त में अक्सर सनातन कहा जाता है। यहां सनातन शब्द हिंदू धर्म की शाश्वत प्रकृति को इंगित करने वाले विशेषण के रूप में काम करता है।'' घोषणापत्र में कहा गया कि कई शिक्षाविद और बुद्धिजीवी अज्ञानतावश हिंदुत्व को हिंदू धर्म के विपरीत के तौर पर चित्रित करते हैं। घोषणापत्र में कहा गया, ''लेकिन अधिकांश लोग हिंदू धर्म के प्रति अपनी गहरी नफरत और पूर्वाग्रहों के कारण हिंदुत्व विरोधी हैं। राजनीतिक एजेंडे और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित कई नेता भी उस समूह में शामिल हो गए हैं और कटुता के साथ सनातन धर्म या सनातन की आलोचना कर रहे हैं।'' विश्व हिंदू कांग्रेस ने ऐसी आलोचना की निंदा की और दुनिया भर के हिंदुओं से आग्रह किया कि वे इस तरह की कट्टरता में शामिल लोगों पर काबू पाने के लिए एकजुट हों और विजयी बनें। हम आपको बता दें कि यह घोषणापत्र ऐसे समय अपनाया गया है, जब कुछ समय पहले द्रमुक नेताओं ने 'सनातन का उन्मूलन' विषय पर एक संगोष्ठी में सनातन धर्म के बारे में कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की थीं।

आरएसएस के नेता दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू समुदाय की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए विभिन्न हिंदू संगठनों के बीच बेहतर समन्वय की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि संगठनों की भिन्नता के कारण ही कई देशों में हिंदू लोग अलग-थलग हो गए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करते हुए आरएसएस महासचिव होसबाले ने कहा कि समाज के सामने मुंह बाए खड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए विश्व स्तर पर हिंदू संगठनों का मजबूत होना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाषा, पंथ, जाति, उपजाति और गुरुओं के आधार पर विश्व के कई हिस्सों में कई संघ, संगठन और फोरम बन गए हैं तथा एक-दूसरे के कार्यों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। होसबाले ने कहा, %सगंठनों की इस भिन्नता के कारण हिंदू खो गया है। बड़े उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बार हिंदू समाज की भिन्नता के कारण कई स्थानों पर फूट पैदा हुई है। उन्होंने हिंदू समाज की आवाज को प्रभावी तरीके से उठाने के वास्ते मतभेदों और विरोधाभासों को दूर करने के लिए संगठनों के बीच बेहतर समन्वय का आह्वान किया। होसबाले ने कहा, %हिंदू संगठनों को आपस में जानकारी साझा करनी होगी, बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा, आपस में सहयोग करना होगा और नकल से बचना होगा। दोहराव आपको कहीं नहीं ले जाएगा।

भाग लेने वाली विभूतियां

वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के संस्थापक और वैश्विक अध्यक्ष स्वामी विज्ञानानंद ने शंख बजाकर सम्मेलन की शुरुआत की। इसमें 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी, विश्व हिंदू परिषद के महासचिव मिलिंद परांडे, आयोजन समिति के अध्यक्ष सुशील सराफ, भारत सेवाश्रम संघ के कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी पूर्णात्मानंद, हिंदू धर्म टुडे-यूएसए के प्रकाशक सतगुरु बोधिनाथ वेयलानस्वामी, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा विचारक और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय सहित अन्य ने हिस्सा लिया। भारत के पीआईएल मैन के रूप में पहचाने जाने वाले अश्विनी उपाध्याय ने अपने संबोधन के माध्यम से जहां हिंदुत्व शब्द की संपूर्ण व्याख्या की वहीं सनातन धर्म के समक्ष खड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए समाधान का मार्ग भी सुझाया।

नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। प्रधानमंत्री अपनी विनिर्माण सुविधा में चल रहे काम की समीक्षा करने के लिए शहर में थे। **(संबंधित समाचार पृष्ठ 7 पर)**

राजस्थान -199 सीटों पर वोटिंग संपन्न, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे

जयपुर। राजस्थान में 199 सीटों पर हुई वोटिंग समाप्त हो गई है। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। वोटिंग सुबह सात बजे शुरू हुई थी। मतदान के दिन कांग्रेस नेताओं ने सत्ता विरोधी लहर, गारंटी और योजनाओं पर भरोसा करते हुए अपनी सरकार बरकरार रखने का भरोसा जताया, जबकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं का मानना है कि इस बार राजस्थान में कमल खिलेगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। राजस्थान में हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है। हालांकि, कांग्रेस को उम्मीद है कि यह रिवाज इस बार बदलेगा और जनता उसके साथ खड़ी है। वहीं, भाजपा राज बदलने की उम्मीद में है। कुल 200 सीटों में से करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया था।

केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अबकी बार मतदान करते समय जो

पिछले 5 साल दुःख तकलीफ झेला है उसे ध्यान में रखकर मतदान करने वाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें जनता का आशीर्वाद मिला है। फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी...कौन क्या कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सचिन पायलट ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य में कांग्रेस को दोबारा मौका मिलेगा। राजस्थान की जनता पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखेगी और उसके बाद आकलन करके मतदान करेगी। मुझे पूरा विश्वास राजस्थान और बाकी अन्य राज्य में कांग्रेस जीतेगी। हमें सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या मिलेगी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सबसे पहले वोट डालने वालों में से थे।

गहलोत और शेखावत ने जोधपुर में, चौधरी ने बालोतरा में, राजे ने झालावाड़ में और पायलट ने जयपुर में वोट डाला। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में अपने मताधिकार का प्रयोग किया और पार्टी सांसद दीया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर में मतदान किया। कुमारी और राठौड़ उन सात भाजपा सांसदों में शामिल हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

राज्य में कुल 36,101 स्थानों पर 50 हजार से अधिक मतदान केन्द्र बनाए गए थे जहां 5,26,90,146 मतदाता प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद किया।

प्रमुख समाचार

2022 में मोदी की सुरक्षा में हुई थी बड़ी चूक, बठिंडा के एसपी को किया गया निलंबित

नई दिल्ली। 5 जनवरी, 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक के संबंध में बठिंडा के एसपी गुरविंदर सिंह संघा को निलंबित कर दिया गया है। पंजाब गृह मंत्रालय ने शनिवार को सूचित किया। राज्य गृह मंत्रालय के

अनुसार, फिरोजपुर में एसपी ऑपरेशंस के रूप में तैनात सिंह पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक 5 जनवरी, 2022 को हुई, जब मोदी फिरोजपुर के हुसैनीवाला जा रहे थे। वह 5 जनवरी की सुबह बठिंडा में उतरे जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। हालांकि, खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री को सड़क मार्ग लेना पड़ा।

हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किमी दूर जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पता चला कि सड़क कुछ प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉक कर रखी है।

जातिगत जनगणना जरूरी, केंद्र को इसे जनगणना के साथ ही कराना चाहिए

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि किसी भी आरक्षण के लाभ के संदर्भ में कोई निर्णय लेने से पहले जातिगत सर्वेक्षण जरूरी है और इसे

केंद्र सरकार को जनगणना के साथ कराना चाहिए। उन्होंने एक साक्षात्कार में यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं कराई है जो 2021 में होनी चाहिए थी और वह 2024 के आम चुनाव के बाद तक इसे टाल सकती है। उनका यह बयान बिहार सरकार द्वारा जातिगत सर्वेक्षण कराने और वंचित वर्गों के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश करने के कुछ दिनों बाद आया है।

चिदंबरम का कहना था, ''मुझे लगता है कि अगर आरक्षण है, तो जातिगत गणना आवश्यक है। मेरे हिसाब से इसे राष्ट्रीय जनगणना के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों (भाजपा) ने 2021 की राष्ट्रीय जनगणना नहीं कराई है। वे 2024 के चुनावों से पहले ऐसा नहीं करेंगे।''

जम्मू-कश्मीर में कहीं भी स्थिति सामान्य नहीं

जम्मू कश्मीर। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने के दावों की आलोचना की और कहा कि ये देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने शांति की कथित कमी के लिए पूरे क्षेत्र में लगातार हो रही मुठभेड़ों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कहीं पर स्थिति

सामान्य नहीं है। राजौरी में स्थिति सामान्य थी, राजौरी को काफी हद तक हमने आतंकवाद से आजाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे हुकूमत के दौरान राजौरी में कोई एनकाउंटर हुआ होगा। उन्होंने कहा कि जब आप राजौरी, उत्तर कश्मीर की बात करते हैं तो जगह जगह हमें इस प्रकार के एनकाउंटर नजर आते हैं। सके साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, आज भी हमारा एक बहादुर अफसर हॉस्पिटल में लड़ रहा है। जो भी सामान्य स्थिति का दावा कर रहे हैं वे ना सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजौरी मुठभेड़ में सेना के पांच जवान शहीद हुए हैं।

11 टन फूलों से होगी विश्वनाथ धाम की सजावट

वाराणसी। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की तर्ज पर देव दीपावली के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को 11 टन फूलों से सजाने का कार्य हो रहा है। इसके अलावा 27 नवंबर को देव दीपावली की शाम श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर भव्य लेजर शो का आयोजन भी योगी सरकार की ओर से किया जा रहा है। इसमे विश्वनाथ धाम, काशी और भगवान शिव की धार्मिक कथा और गाथा को पर्यटक देख और सुन पाएंगे। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि गंगा द्वार पर लेजर शो के माध्यम से धाम पर आधरित, काशी के महत्व और कॉरिडोर के निर्माण सम्बंधित जानकारी को प्रदर्शित किया जाएगा। लेजर शो की अवधि 5 मिनट की होगी, जो कई बार प्रसारित किया जाएगा। लेजर शो इस तरह से कराया जा रहा है जिससे नौकायन करने वाले और घाटों पर मौजूद लोग आराम से देख सकें।

आदित्य एल1 अपने लक्ष्य के बेहद नजदीक पहुंचा, इसरो चीफ ने बताई अहम जानकारी

हरिकोटा। भारत का महत्वपूर्ण मून मिशन आदित्य एल 1 इन दिनों सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए निकल चुका है। आदित्य एल 1 को लेकर अब नई जानकारी सामने आई है,

जिसको जानकर देश भर में खुशी का माहौल है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के इस बेहद महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य एल 1 से संबंधित नया अपडेट सामने आया है। इसे लेकर खुद इसरो अध्यक्ष ने जानकारी साझा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सूर्य मिशन आदित्य एल 1 को लेकर कहा कि सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन के तहत प्रक्षेपित 'आदित्य एल1' अंतरिक्ष यान अपने अंतिम चरण के करीब है। उन्होंने संभावना जताई कि एल1 बिंदु में प्रवेश करने की प्रक्रिया सात जनवरी, 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है।

संविधान

चौहत्तर साल की यात्रा, इस राह पर 50 देशों से बेहतर है हमारा रिकॉर्ड

चौहत्तर वर्ष पहले 26 नवंबर, 1949 को हमने अपने संविधान को अधिनियमित तथा अंगीकृत किया था। किसी राष्ट्र के जीवन काल में यह बहुत बड़ा कालखंड नहीं माना जाता, किंतु इन वर्षों में उस राष्ट्र के भविष्य की पीठिका तैयार हो जाती है। संविधिक विकास के लिहाज से शुरुआती कुछ दशक अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनमें कानूनी व्यवस्था का नया ढांचा तैयार होता है, उसे आत्मसात करने की परंपरा विकसित की जाती है तथा कानून की न्यायिक व्याख्या की दिशा तय होती है। संविधान के माध्यम से हमने अपने राष्ट्र को प्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का संकल्प लिया। हमने ऐसे समाज की परिकल्पना की, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता के साथ ही सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो।

संविधान आजादी और खुशहाली के वादे का दस्तावेज होता है। संविधान हमें सपने देखने और उसके मुताबिक समाज निर्माण करने की आजादी और जज्बे को भी निरूपित करता है। उसमें केवल काले-सफेद अक्षरों की भरमार नहीं होती, बल्कि वह सुशासन के लिए लिपिबद्ध भावपुंज भी होता है। लेकिन उसे मजबूती देने के दायित्व का निर्वहन उसके नागरिकों को करना होता है। हमारे संविधान के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने रामराज्य का सपना देखा था, जिसमें सभी समान हों। सभी लोग कानून की मर्यादा में रहें। राज्यसत्ता को राम की खड़ाऊं मानकर तथा अपने आपको उसका सेवक मानकर जनता की सेवा करें। कानून का पालन निष्पक्षतापूर्वक हो। निर्णय लेते समय किसी का भय न हो तथा किसी वस्तु का लालच उन्हें विचलित न कर सके।

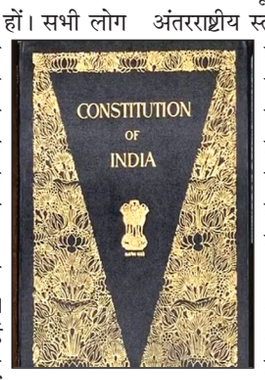

बीते वर्षों में हमने संविधान के तमाम आदर्शों के पालन का प्रयास किया है। और अधिकतर मामलों में हमारा रिकॉर्ड शानदार रहा है। हमारे साथ आजाद हुए करीब 50 देशों में से कहीं भी लोकशाही वहां के जनजीवन में वह पैठ नहीं बना पाई है, जो हमारे देश में बनी है। हमारे पड़ोसी देशों-पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे किसी भी देश में लोकतंत्र कभी खुली हवा में सांस नहीं ले पाया। वह हर समय सैनिक तानाशाही की संगीनों से भयभीत रहा। इस बीच हम सत्रह बार आम चुनावों के माध्यम से केंद्र की सत्ता के शालीन हस्तांतरण के गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी रहे हैं। आम आदमी का जीवन स्तर बेहतर हुआ है। भारतीयों ने पूरे विश्व में अपनी क्षमता की छाप छोड़ी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सम्मान से देखे जाते हैं। इसके बावजूद कुछ ऐसे क्षण आए हैं, जब हमने संविधान की मर्यादा से छेड़छाड़ की है, उसे चोट पहुंचाई है और उसकी अवमानना की है। हमारे इस आचरण ने संविधान की प्रतिष्ठा और हमारे लोकतंत्र को चोट पहुंचाई है। हमें उन पर ध्यान देने की जरूरत है। उन दोषों के परिकरण की आवश्यकता है।

हमारा संविधान सामाजिक और आर्थिक न्याय का जीवंत दस्तावेज है। आजादी के बाद के वर्षों में किए गए प्रयास इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जमींदारी उन्मूलन जैसी ऐतिहासिक उपलब्धियां राष्ट्र के खाते में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हैं। विश्व के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब कुछ हजार जमींदारों से जमीन लेकर लाखों भूमिहीन किसानों को दे दी गई और यह सब कुछ बगैर किसी का खून बहाए हुए शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है, जहां इतने व्यापक भूमि सुधार इतने शांतिपूर्वक संपन्न हुए हों। कम्युनिस्ट देश अपने लाखों नागरिकों का खून बहाकर भी भूमि सुधारों के क्षेत्र में जो कुछ हासिल करने में सफल नहीं हो पाए, उसे हमने शांतिपूर्वक लागू कर दिया, जिसका लाभ आज पूरे देश को मिल रहा है।

शिक्षा सामाजिक उन्मेष की आधारशिला है। यह ज्ञान की नई दुनिया का प्रवेश द्वार खोलती है, स्वतंत्र विचारधारा विकसित करने में मदद करती है, भ्रांतियों के अंधकार से बाहर निकालती है और आत्मविश्वास व स्वाभिमान में वृद्धि करती है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21(क) के रूप में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है। राज्यों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के प्रयास हो रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, उसे आगे बढ़ने में कोई बाधा न रहे। यह बहुत बड़ा कदम है।

संविधान का अनुच्छेद 370 और अदृश्य अनुच्छेद 35(अ) हमारे मर्मस्थल पर चुभे हुए कांटे जैसा था। चार वर्ष पहले इस दिशा में की गई सार्थक पहल ने समता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान को व्यापकता दी। जम्मू-कश्मीर के अलगावावाद से निपटने में आने वाली सबसे बड़ी बाधा दूर हुई। एक राष्ट्र, एक विधान और एक निशान का संकल्प पूरा हुआ। अब वहां जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। देश के दूसरे हिस्से की तरह अब वहां पर शेष भारत का कोई भी व्यक्ति बस सकता है और संपत्ति खरीद सकता है। महिलाओं को बराबरी का हक हासिल हुआ और वंचित-शोषित लोगों को आरक्षण का अधिकार मिला। अनुच्छेद 370 और 35(अ) हमारी राजनीतिक पराजय का प्रतीक था। देश ने उसे संविधान से हटाकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि किसी भी देश के संविधान की सफलता उस देश के नागरिकों तथा संविधान को चलाने वालों के चरित्र और उनकी नीयत पर निर्भर करती है। उन्होंने आगे कहा था कि चाहे कितना भी अच्छा संविधान क्यों न हो, यदि उसके चलाने वालों में संविधान के मूल्यों के प्रति समर्पण और उसे लागू करने का जज्बा न हो, तो संविधान निर्जीव अक्षरों का समूह मात्र बना रहेगा। इसके उलट यदि किसी संविधान में कोई कमी रह गई हो, किंतु उसका पालन करने वाले लोग यदि संविधान के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान हैं, तो उन कमियों को दूर करके जीवंत समाज का निर्माण करेंगे। पिछले 74 वर्षों के हमारे अनुभव ने डॉ. आंबेडकर के कथन को अक्षरशः सही होते हुए देखा है। संविधान के उच्च आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा ने बीते वर्षों में हमें अग्रिम पंक्ति तक पहुंचा दिया है। हम केवल वहीं विफल हुए हैं, जहां हमारे नागरिकों और शासक वर्ग ने संविधान के मूल्यों की अनदेखी की है।

चालीस साल बाद कांकेर में बदला मतगणना स्थल, छात्रों के विरोध की वजह से झुका प्रशासन

कांकेर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 3 दिसंबर को मतगणना होनी है।इस दिन कांकेर जिले की तीन विधानसभा सीटों पर भी मतगणना होगी।लेकिन इस बार मतगणना स्थल बदल चुका है। पहले तीन विधानसभाओं के लिए मतगणना के लिए पीजी कॉलेज को चुना जाता था। इसी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाकर तैयारियां की जाती थी।लेकिन इस बार शहर से 10 किलोमीटर दूर पॉलीटेक्नीक कॉलेज में मतगणना होगी।

आपको बता दें कि 40 साल बाद कांकेर में मतगणना स्थल बदला गया है। इससे पहले कांकेर के पीजी कालेज में मतगणना होती थी। लेकिन पीजी कॉलेज को चुनाव कार्यो के लिए अधिग्रहण करने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। पढ़ाई प्रभावित होने से छात्रों को काफी परेशानी होती थी।जिसका विरोध कई सालों से छात्र कर रहे थे। इस बार भी जब पीजी कॉलेज को चुना जाना था,तो छात्रों ने विरोध किया।आखिरकार जिला प्रशासन ने पीजी कॉलेज के बजाए पॉलीटेक्निक कॉलेज को मतगणना के लिए चुना।

मीडिया ने पीजी कॉलेज के छात्रों से बात की।जिसमें उन्होंने बताया कि लगातार जब भी चुनाव होता था तो पीजी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया जाता था। जहां से सामान वितरण और मतगणना होता था। अधिसूचना जारी होने के बाद से ही कॉलेज का अधिग्रहण कर लिया जाता था।जिससे परीक्षा की तिथि के साथ पढ़ाई पर भी असर पड़ता था।

कॉलेज स्टूडेंट राकेश ने कहा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती

थी। जिसका असर परीक्षा के परिणाम में भी दिखता था।हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था। हम लगातार विरोध करते आ रहे थे। हमारे विरोध के कारण इस बार पीजी कॉलेज से स्ट्रांग रूम और मतगणना के कार्य को हटाकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। अब हमारी पढ़ाई अच्छे से हो रही है।लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। जहां के छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही होगी।

छात्रों की मांग है कि किसी भी कॉलेज को चुनाव के लिए अधिग्रहण न करके किसी सरकारी भवन में स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल बनाया जाए। वहीं कांकेर कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 2022 में हमने बाय इलेक्शन नवंबर दिसंबर में कराया था। उस समय 4 महीने करीब कॉलेज हमारे अधिग्रहण में था। उस वक्त एक बात सामने आई थी कि हर बार पीजी कॉलेज को ही स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है। जिससे पढ़ाई प्रभावित होने की बात सामने आती थी। इस बार कोई ऐसी संस्था में स्ट्रांग रूम बनाया गया। जहां कम से कम पढ़ाई प्रभावित हो।इसलिए हम लोगों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज का चयन किया है।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा मैंने और एसपी ने दो-तीन बार निरीक्षण भी किया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी पढ़ाई किसी तरीके से प्रभावित न हो। उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। निर्वाचन आयोग का जो भी दिशा निर्देश है उन सारे दिशा निर्देशों का पालन करके हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज के अधिग्रहण किया है।

कांकेर नगर के पीजी कॉलेज को 1984 के बाद से हर बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित किया जाता था। चुनाव के लिए अधिग्रहण होने से तीन से चार महीने तक पढ़ाई ठप होती थी। दिसंबर 2022 के भानुप्रतापपुर उपचुनाव के दौरान भी कॉलेज भवन अधिग्रहित था। लगातार पढ़ाई नुकसान होने से छात्रों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला था।क्योंकि मतगणना के बाद भी दो माह तक ईव्हीएम स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे जाते थे।इसलिए इस दौरान पढ़ाई नहीं होती थी।

कांकेर में ब्लूटूथ स्पीकर को जवानों ने समझा आईईडी

■ जियो टावर पर लगाए थे बैनर पोस्टर, पीएलजीए सप्ताह मनाने की अपील

कांकेर। नक्सलियों ने जिले के बांदे थाना क्षेत्र अंतर्गत पीव्ही 91 चितरंजन नगर गांव के जियो टावर के पास बैनर पोस्टर लगाए थे।इसी दौरान जब जांच दल मौके पर पहुंचा तो उन्हें एक वायर दिखाई दिया।जो एक डिवाइस से कनेक्ट था।आईईडी की आशंका जाहिर करते हुए सुरक्षा बलों की जांच टीम ने मौके पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया।

नक्सलियों ने जिस डिवाइस को वायर से कनेक्ट किया था।उसे जांच करने के लिए बीएसएफ जवानों के साथ बम स्क्वॉड भी पहुंचा था।इस दौरान हर तरह से डिवाइस की जांच की गई।तीन घंटे बाद जब जांच दल ने करीब से जाकर डिवाइस का निरीक्षण किया तो पता चला जिसे टीम आईईडी समझ रही थी।वो एक ब्लूटूथ स्पीकर था।

आपको बता दें कि 16 नवम्बर को छोटेबेटिया थाना क्षेत्र में चितरंजन गांव में नक्सलियों ने जियो टावर में आगजनी की थी।जिसमें मोबाइल टावर के जनरेटर को नुकसान पहुंचाया गया था। उसी जगह पर

नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया था। जहां बीएसएफ के जवान घटना स्थल में सर्चिंग कर रहे थे।वायर दिखने पर आईईडी होने की आशंका हुई। लेकिन 3 घंटे सर्च करने पर ब्लूटूथ स्पिकर मिला। नक्सली बैनर पोस्टर के माध्यम से पीएलजीए 23वी वर्षगांठ 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक मानने अपील कर रहे हैं। कांकेर के आमाबेड़ा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। डीआरजी और बीएसएफ के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे। तभी नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में जवान नक्सलियों पर भारी पड़े।जवानों को खुद के ऊपर भारी पड़ता देख नक्सलियों ने मैदान छोड़कर भागने में ही भलाई समझी।इसके बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए।

झोलाछाप डॉक्टर ने ली मासूम बच्चे की जान, इलाज में बरती लापरवाही

चुप रहने के लिए दिए दस हजार रुपये

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में गोरेला ब्लॉक के ठेंगाडांड़ गांव में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से छह साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, बच्चे को मामूली बुखार था, झोलाछाप डॉक्टर ने लापरवाही पूर्वक इलाज कर उसके नस में कोई दवा चढ़ाई और उसके बाद कुछ ही समय के बाद मासूम की मौत हो गई।

गौरेला विकासखंड के ठेंगाडांड़ गांव में मंगल सिंह राठौर के घर में छह साल के मासूम अंकुश राठौर की 23 अक्तूबर की रात हल्का बुखार आया जिसके बाद अगले दिन बच्चे के माता-पिता उसे खोडरी गांव में इलाज करने वाले झोलाछाप डॉक्टर राम सिंह राठौर के निजी क्लीनिक लेकर पहुंचे जहां पर बिना कुछ जांच पड़ताल एवं बिना किसी प्रशिक्षण के झोलाछाप डॉक्टर राम सिंह राठौर ने बच्चे के नस में एच शेड्यूल का एंटीबायटिक मोनोसेफ 500 इंजेक्शन लगाया जिसके तुरंत बाद मासूम बच्चे की तबीयत और बिगड़ने लगी तो झोलाछाप डॉक्टर राम सिंह राठौर ने तुरंत उसको डेकसोना (जीवन रक्षक) इंजेक्शन लगा दिया। तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो ड्रिप चढ़ाने लगा शरीर ठंडा पड़ने लगा और जब बच्चा शांत हो गया तो, तो झोलाछाप डॉक्टर राम सिंह राठौर ने बच्चे और उसके परिवार के लोगो को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

गौरेला में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पास पहुंचा। सशिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक ने बच्चे को मृत बताया। बच्चे की मौत के बाद झोलाछाप डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि कहीं भी शिकायत करोगे तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा यह कहते हुए उन्हें शांत रहने के लिए दस हजार रुपये भी दिया।

स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था का परिणाम झोलाछाप डॉक्टर है,और यह झोलाछाप डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की फैली अवस्थाओं का फायदा उठा कर गांव-गांव में प्रतिदिन ना जाने कितने ही लोगों की जान से खेलते हैं और इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य अमला ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात करता है परंतु कभी परिणाम तक नहीं पहुंच पाता।

बेमेतरा में चार साल से है मुआवजे का इंतजार अफसर की लापरवाही परिजनों पर भारी

बेमेतरा। शहर के मोहभट्टा वार्ड में 21 नवंबर 2019 को तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर तालाब में डूब गई थी। हादसे में देवरी गांव के रहने वाले एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई थी। चार साल पहले हुए हादसे के पीड़ितों को आज तक मूल सहायता राशि नहीं मिल पाई है। परिजनों का कहना है कि वो मदद पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। अफसर कभी उसके पास तो कभी इसके पास भेजकर लौटा देते हैं। पीड़ित परिवार में अब दो बुजुर्ग और एक बच्चा बचा है। परिवार में कमाने वाले की मौत के बाद से पूरा परिवार मुफलिसी की जिंदगी जी रहा है। परिवार को आज भी उम्मीद है कि एक दिन सरकारी कर्मचारियों को उनपर दया आएगी और वो उनको मुआवजे की रकम जरूर देंगे।

पीड़ित परिवार के मुताबिक पूरा परिवार जन्मदिवस की पार्टी मनाकर घर लौट रहा था, तभी उनकी कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की डूबने से मौत हो गई। परिवार ने मदद के लिए प्रशासन ने मुआवजा मांगा पर प्रशासन ने सिर्फ तात्कालिक मदद देकर परिवार के बुजुर्ग को चलता कर दिया। परिवार के बुजुर्ग सदस्य गणेश टंडन ने कहा कि, राहत राशि के लिए वो दर दर की ठोकरे खा रहे हैं। अफसर कभी

इसके पास भेजते हैं तो कभी उसके पास। मुआवजा मिला नहीं उलटे भाग दौड़ से खर्च अलग बढ़ गया। कभी दस लोगों का लंबा परिवार हुआ करता था, हादसे के बाद सिर्फ तीन लोग बचे हैं।मदद के लिए अब परिवार ने कोर्ट की शरण ली है। वकील की कोशिश है कि कोर्ट के जरिए अब इनको न्याय मिले।

पीड़ित परिवार चार साल से मदद के लिए भटकते भटकते परेशान हो चुका है। नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे ने जरूर अपनी ओर से 50 हजार रुपये की मदद परिवार को दी है। बेमेतरा कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि फाइल मंगाकर जांच कर रहे हैं। फील्ड से अगर दस्तावेज मिले होंगे तो जरूर मदद की बाकी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

यात्रियों की जान हथेली में लेकर बस दौड़ा रहा था नशेड़ी ड्राइवर

■ लोगों को मारी ठोकर, पुलिस ने ऐसे बचाई सवारियों की जान

बलौदाबाजार। पुलिस की सक्रियता से बस में बैठे यात्रियों की जान बचाई है और एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। पलारी पुलिस को लोगों ने सूचना दी कि रायपुर से बलौदाबाजार की ओर आ रही गुरु कृपा ट्रेवल्स बस का चालक शराब के नशे में बस को लहराते हुए चला रहा है। जिससे सड़क पर चलने वाले कुछ लोगों को ठोकर मारते और दुर्घटना कारित करते-करते बचा है।

सूचना पर पुलिस ने बस का पीछा कर ग्राम अमेरा के पास रुकवाया। जिसके बाद बस चालक को बस से उतरवा। उस समय वह काफी नशे में था साथ ही कंडक्टर ने भी नशा कर रखा था। नाम पूछने पर चालक ने अपना नाम राजकुमार लूनिया पिता मनोहर लाल उम्र 33 साल निवासी खरौद थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर-

चांपा बताया। बस क्र। सीजी15 एबी 0226 और बस चालक को थाना पलारी लाया गया आरोपी बस चालक के विरुद्ध धारा 185 एमवी एक्ट की कार्रवाई की गई। साथ ही शराबी बस चालक के विरुद्ध धारा 279 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए पृथक से धारा 151,107/116 जा।फौ। के तहत भी कार्रवाई की गई है। बस में बैठे लोगों ने पलारी पुलिस को धन्यवाद दिया। बता दें कि बलौदाबाजार जिले से सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन बसें राजधानी सहित आसपास के जिलों में चलती है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आवागमन करते हैं। ऐसे में आज की घटना सवाल पैदा करती है कि बस मालिक ऐसे चालकों को वाहन चलाने क्यों देते हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पार्षद देव, कांग्रेस नेता तरुण व बग्गा 6 वर्षों के लिए निष्कासित

महासमुंद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पिथौरा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते पिथौरा नगर के पार्षद देव सिंह निषाद, तरुण पांडे व कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह बग्गा (राजा बग्गा) को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही नगर पंचायत पिथौरा के एल्डरमेन लक्ष्मीकांत सोनी, जिला कांग्रेस कमेटी तथा जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, कांग्रेस नेता मोहित ध्रुव, अंकित बागबाहरा के निष्कासन हेतु प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा गया है। कल पिथौरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष करण सिंह दीवान की उपस्थिति में बैठक हुई। जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त नेताओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग हुई। इस दौरान करण सिंह दीवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी से महत्वपूर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं है। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ कार्य किया है। उन्हें तत्काल 6 वर्षों के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निष्कासित करती है।

गजराज बने यमराज, नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक

बलरामपुर। जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि, जंगली हाथी ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में तबाही मचा रहे हैं। इसी बीच एक हाथी अपने दल से बिछड़ गया। जिसने एक ग्रामीण को कुचलकर मार दिया। ये घटना तब घटी जब ग्रामीण अपने खेत में धान की पहरेदारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार, हाथी को देखकर ग्रामीण भागने लगा। तभी हाथी ने दौड़ाकर कुचल दिया। पूरा मामला शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के ग्राम लडुवा का है। मौके पर वन अमला मौजूद है।

स्टील प्लांट में महिला अधिकारी ने ट्रेनी के सिर पर मारा टिफिन

भिलाई। एशिया के सबसे बड़े प्लांट भिलाई स्टील प्लांट में एक महिला अधिकारी ने ऑफिस में जमकर तांडव मचाया। इस्पात भवन में महिला अधिकारी के द्वारा किए गए उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा है। जिसमे एजीएम (असिस्टेंट जनरल मैनेजर) प्रियंका होरो ने ऑफिस के अंदर जमकर हंगामा करती नजर आ रही हैं। महिला अधिकारी ने दफ्तर में रखा कंप्यूटर, सीटीटीवी कैमरे को तोड़ती नजर आ रही हैं। वहीं टेबल में रखे दस्तावेजों में पानी डालने जैसी हरकतें की ये पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इतना ही नहीं महिला ट्रेनी के सिर पर टिफिन फेंककर उस पर हमला कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसपी ने महिला अधिकारी को सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के महिला जवानों को बुलाया गया जहां महिला अधिकारी ने सीआईएसएफ के महिला कांस्टेबल के साथ भी बदतमीजी की। महिला अधिकारी के उत्पात से सह कर्मियों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की है।

ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन पड़ेगा महंगा

कोरबा। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर आपने ज्वलनशील पदार्थों को अपने साथ रखा है तो आपकी खैर नहीं, रेलवे ने साफ तौर पर कह दिया है कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ का परिवहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी रेलवे के द्वारा इस दिशा में लगातार निगरानी भी की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जा रही है। कोरबा की रेलवे पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान अगर किसी यात्री के पास ज्वलनशील पदार्थ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनों में हाल ही के दिनों में आगजनी की कुछ घटनाएं सामने आई है जिसे लेकर रेलवे प्रबंधन काफी गंभीर हो गया है और हरहाल में नियमों का पालन कराने को लेकर प्रयास कर रहा है। रेलवे आरपीएफ थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रेन में अगर कोई यात्री केरोसिन, गैस सिलेंडर और विस्फोटक सामान का परिवहन करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सगाई की खुशियां मातम में बदल गई

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई। जिले ठेलकाडीह थाना क्षेत्र में शनिवार को सगाई का निमंत्रण देने जा रहे दो युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में सगाई की खुशियां मातम में बदल गई है। ठेलकडीह थाना अंतर्गत ग्राम सिरसाही में दो मोटर साइकिल में आमने सामने भिड़ंत हो गई और इस हादसे में दुर्घटना में ग्राम कोपे नवागांव निवासी 18 वर्षीय प्रकाश वर्मा और एक अन्य युवक की मौत हो गई। वहीं दो लोगों को गंभीर चोटें आई है। मृतक दोनों युवक सगाई का निमंत्रण देने निकले थे। मृतक और घायल सिर में हेलमेट नहीं पहने थे।

सड़क चौड़ीकरण का काम रुका, चंद दुकानदारों की वजह से लगता है जाम

बैकुंठपुर। जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे सड़क चौड़ीकरण किया जाना था। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाए जाने के लिए जो पहले से बिजली के खंभे लगे थे उनको हटाना था। साल 2019 में कुछ बिजली के पोल को हटाया गया, लेकिन ओड़गी नाका से लेकर कुमार चौक तक करीब 40 बिजली के पोल ऐसे हैं जिनको आज तक नहीं हटाया जा सका। बिजली खंभों की शिफ्टिंग नहीं होने से सड़क चौड़ीकरण का काम तो रुका ही, साथ ही जाम के हालत आज भी बने हुए हैं।

स्थानीय लोगों की शिकायत है कि जाम के चलते लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है, सड़क दुर्घटनाएं अलग बढ़ गई हैं। लोगों की शिकायत है कि महज 10 फीसदी लोगों के चलते शहर के 90 फीसदी आबादी को जाम की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर बायपास शहर के बाहर से होकर गुजरे तो

जाम के हालात नहीं बनेंगे। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक भी एनएच होने के चलते गाड़ियों को निकलने में कई घंटे लगते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात के सात बजे तक सड़कों पर बड़ी गाड़ियों का दबाव ज्यादा होता है। नगर पालिका की टीम पर आरोप है कि वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समय समय पर करती रहती तो आज ये हालात नहीं बनते। शिकायत ये भी है कि हाईवे के किनारे कुछ दुकानदारों ने तो पांच पांच फीट तक सड़कों पर कब्जा जमा लिया है। अतिक्रमण के चलते सड़क अब गली में तब्दील हो गई है।

स्थानीय व्यापारी अनुराग दुबे ने कहा शहर में सड़कों का चौड़ीकरण जरूरी है। बायपास तो हर शहर में होता है लेकिन मुख्य मार्ग से जाम की समस्या से निपटना जरूरी है। सरकार चाहे किसी की भी हो चौड़ीकरण का मुद्दा सबसे प्रमुख मांग है। सड़क चौड़ी होती है तो इससे शहर का विकास होगा, लोगों को जाम से राहत मिलेगी।

जाम को खत्म करने और सड़कों को चौड़ी करने के लिए पूर्व कलेक्टर डोमन सिंह ने बिजली के खंभों की शिफ्टिंग के लिए राशि देने की बात कही थी। वर्तमान में बिजली विभाग का कहना है कि उनको बिजली के पोल की शिफ्टिंग के लिए आज तक बजट राशि नहीं मिली। बिजली विभाग के अफसरों की दलील है कि अगर बजट मिल जाता तो काम जल्द शुरु कर देते। सड़क को दुरुस्त करने के लिए पिछले साल 13 दिसंबर को खरवत चौक से लेकर जमगहना चौक तक की 13 किलोमीटर की सड़क की नापी हुई। सर्वे का काम पूरा होने के बाद इसको मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया।

ग्रैंड विजन फर्म के पार्टनर ने की 2 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी

राजनांदगांव। केबल कारोबार के नाम पर 2 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले तीन लोगों के खिलाफ बसंतपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

पुलिस के मुताबिक आरोपी आकाश दास राजनांदगांव का रहने वाला है। वह ग्रैंड विजन के साथ राजनांदगांव में केबल का संचालन करता था। पिछले कुछ समय से फर्म के हिसाब-किताब में कई गड़बडियां सामने आ रही थी। इस संबंध में आकाश से जानकारी मांगी गई, तो वह हिसाब देने में टालमटोल करने लगा। बार-बार कहने के बाद भी हिसाब नहीं दिया, तो इसकी जांच की गई। इसमें फर्म के हिसाब मिलान करने पर 2 करोड़ 74 लाख रुपए से ज्यादा गड़बड़ी पाई गई। दरअसल केबल ग्राहकों से शुल्क लिया गया, लेकिन उसे फर्म में जमा नहीं किया गया है, इसमें मुख्य आरोपी आकाश दास के अलावा उसके साथी राजीव पंजियारा और नंदू भूतरा भी शामिल हैं। आकाश ने ग्रैंड विजन की 2 करोड़ 74 लाख से ज्यादा की राशि को राजीव और नंदू के खाते में अंतरित कर दिया था, जबकि दोनों आरोपियों का ग्रैंड विजन से कोई नाता नहीं था। इस तरह सभी आरोपियों ने मिलकर ग्रैंड विजन के ग्राहकों से प्राप्त राशि को फर्म में जमा न करके पूरी राशि का गबन कर लिया। इसके बाद सभी फरार हो गए है। इसकी शिकायत पर बसंतपुर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 120 बी और 409 के तहत धोखाधड़ी समेत फर्जी दस्तावेज बनाने का अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

सीएम बघेल ने मनाई 'बढ़ौना' रस्म, बोले- इस बार अच्छी हुई धान की पैदावार

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज अपने खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखी। इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है। दरअसल सीएम बघेल खेती-किसानी से जुड़े हैं और बघेल समय-समय पर फसलों और उनकी पैदावार की जानकारी लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को सपरिवार गांव कुरुदडीह स्थित अपने खेतों में पहुंचकर 'बढ़ौना' रस्म का निर्वहन किया। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर फोटो शेयर किया है। खेतों में फसलों की लुआई पूरी होने पर मनाए जाने वाले 'बढ़ौना' की रस्म को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने लिखा कि धानवान छत्तीसगढ़! आज अपने खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखी। इस बार धान की अच्छी पैदावार हुई है। महतारी की कृपा सब पर बनी रहे।

महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस रविवार को मनाया जायेगा

रायपुर। वैदिक सत्संग समिति एवं पतंजलि के संयुक्त तत्वावधान में वृंदावन हॉल में रविवार को प्रात: 10 बजे बजे महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस मनाया जायेगा। विश्व प्रसिद्ध आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री विशेष उद्बोधन देने दिल्ली से आ रहे हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजन समिति के अध्यक्ष राकेश दुबे ने बताया वर्तमान समय में हम सभी सनातन धर्म पर हो रहे वार से दुखी हैं। समस्त हिंदू समाज को संगठित होकर सनातन धर्म की गरिमा को पुनः स्थापित करना होगा। सनातन धर्म का मूल चार वेद है महर्षि दयानंद ने वेदों को सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया है। कार्यक्रम को अनेक वैदिक विद्वान संबोधित करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में 60 से अधिक पुस्तकों के लेखक आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री दिल्ली से पधार रहे हैं।

2 दिसम्बर से 29 फरवरी तक सारनाथ एक्सप्रेस रहेगी रद्द

रायपुर। उत्तर भारत में शरद ऋतु में कोहरे के चलते रेलवे द्वारा एहतियातन ट्रेनों को रद्द किया जाता है लेकिन कोहरा अभी शुरू भी नहीं हुआ और रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने की सूचना देना शुरू कर दिया है। रेल प्रबंधन के मुताबिक घने कोहरे की वजह से दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली सारनाथ एक्सप्रेस 2 दिसंबर से 29 फरवरी 2024 के बीच कई दिन तक रद्द रहेगी। 15159 छपरा से दुर्ग- दिसम्बर में 02, 04, 06, 09,11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, एवं 30 को। जनवरी 2024 में 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 एवं 31 को। फरवरी 2024 में 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 एवं 28 को। दुर्ग से छपरा-दिसम्बर में 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 एवं 31 को। जनवरी 2024 में 02 04, 07, 09, 11,14 16,18, 21, 23, 25, 28 एवं 30 को। फरवरी में 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 एवं 29 फरवरी को रद्द रहेगी।

28 नवंबर से छात्रों को इंडोर स्टेडियम से मिलेगा ऑफलाइन टिकट

रायपुर। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 1 दिसंबर को होने वाले भारत- ऑस्ट्रेलिया टी 20 मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखा रहा है। शुक्रवार को पेटीएम में बुकिंग शुरू होने पर शाम तक जनरल टिकट आधे से अधिक बुक हो गए। वहीं छात्रों को 28 नवंबर से इंडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे से टिकट मिलना शुरु हो जाएगा। क्रिकेटप्रेमी पेटीएम और पेटीएम इनसाडर ऐप के माध्यम से अपनी टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे है। एक परिचय पत्र से चार टिकट बुक करा सकते है। दर्शक अपने फिजिकल टिकट इंडोर स्टेडियम से ले सकेंगे। छात्रों को केवल ऑफलाइन टिकट बेचा जाएगा। 28 नवंबर से छात्रों को इंडोर स्टेडियम में सुबह 11 बजे से टिकट मिलने शुरू होंगे। परिचय पत्र दिखाने पर छात्र 1000 रुपए में टिकट खरीद सकेंगे। एक परिचय पत्र पर एक टिकट ही खरीद सकेंगे। जनरल कैटेगरी की अपर लेवल में 1300 सीटों का कोटा छात्रों के लिए निर्धारित है। पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर छात्रों को टिकट मिलेगा।

27 और 28 नवंबर को बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में बारिश की संभावना

रायपुर। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और आने वाले सप्ताहभर तक इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना है। कुछ जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 27 और 28 नवंबर को बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों में बारिश की संभावना भी है।

दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग एक्सप्रेस 3 दिसंबर को रद्द, भगत की कोठी रिश्यूडल

रायपुर। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉलटयर रेल मंडल में पलासा-विशाखापत्तनम और रायगड़ा-विजयनगरम सेक्शन पर आईएचएस कार्यों और स्टोन स्लैब पुलों के पुनर्निर्माण के संबंध में कट और कवर विधि द्वारा आरसीसी सेगमेंटल बॉक्स लगाने के लिए ट्रैफिक सह पावर ब्लॉक के लिए जाने के कारण कोचिंग ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 3 दिसंबर को गाड़ी संख्या 18529/18530 दुर्ग- विशाखापट्टनम- दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रहेगी। 18574 भगत की कोठी-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस को 3 दिसंबर को भगत की कोठी स्टेशन से 7 घंटे रीशेड्यूल किया जाएगा। 2 दिसंबर को 20.30 बजे रवाना होने के बजाय 3 दिसंबर 2023 को 3.30 बजे रवाना किया जाएगा।

महादेव एप मामले में गिरफ्तार एजेंट का किसी भी नेता को पैसे देने से इन्कार

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने विशेष अदालत में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया और उसे फंसाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नकदी पहुंचाने के आरोप का सामना कर रहे असीम दास और पुलिस आरक्षक भीम सिंह यादव को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से चार दिन पहले तीन नवंबर को गिरफ्तार किया था। राज्य में 7 और 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान हुआ। मतगणना तीन दिसंबर को होगी। दास के वकील शोएब अल्वी ने बताया कि दास और यादव को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया गया।

उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत सात दिन के लिए बढ़ा दी। अल्वी ने बताया कि दास ने जेल से ईडी के निदेशक को एक पत्र लिखा था और इसकी प्रतियां 17 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय और अन्य उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई।

पत्र में कहा गया है कि उसे महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में फंसाया जा रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसी ने उसे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिस भाषा को वह नहीं समझता है। वकील ने बताया कि उन्होंने अदालत से इस पत्र को इस मामले में रिकॉर्ड पर स्वीकार करने का आग्रह किया है।

दास ने अपने पत्र में कहा है कि वह इस साल अक्टूबर में शुभम सोनी द्वारा बुलाए जाने के बाद दो बार दुबई गया था, जो उसके बचपन का दोस्त था। यात्रा की व्यवस्था सोनी ने की थी। ईडी के अनुसार सोनी महादेव नेटवर्क के मुख्य आरोपियों में से एक है। अल्वी ने बताया, ''दास ने पत्र में कहा है कि सोनी छत्तीसगढ़ में एक निर्माण व्यवसाय शुरू करना चाहता था और उसने उसे (दास को) अपने लिए काम करने कहा था। सोनी ने दास को धन की व्यवस्था करने का वादा किया था।''

अल्वी ने कहा, ''उस दिन (जब दास को गिरफ्तार किया गया था) उसे (दास को) रायपुर विमानतल की पार्किंग में खड़ी एक कार लेने और रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित एक होटल में जाने के लिए कहा गया था। बाद में उसे कार को सड़क पर पार्क करने के लिए कहा गया, जहां एक व्यक्ति ने नकदी से भरा बैग कार में रखा और चला गया।''

दास ने पत्र में कहा है, ''मुझे फोन पर अपने होटल के कमरे में वापस जाने के लिए कहा गया और कुछ ही देर में ईडी के अधिकारी मेरे कमरे में आए और मुझे अपने साथ ले गए। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे फंसाया जा रहा है।'' दास ने कहा है, मैंने कभी भी किसी नेता या कार्यकर्ता को धन या कोई अन्य सहायता नहीं दी है।

तीन नवंबर को सामने आया था आरोपी का बयान

मालूम हो कि ईडी ने तीन नवंबर को दावा किया था कि फॉरेंसिक विश्लेषण और नकदी पहुंचाने के आरोपी दास द्वारा दिए गए एक बयान से चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और यह जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने आरोप से इनकार किया था और भाजपा पर विधानसभा चुनाव में हार की आशंका में ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

मेकाहारा में छत्तीसगढ़ के पहले सफल ऑपरेशन से मासूम को मिला नया जीवन

डॉक्टर ने सफल सर्जरी कर 3 साल की बच्ची के फेफड़े से निकाला 1.5 किलो का ट्यूमर

रायपुर। डॉ। भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग में 3 साल की बच्ची के छाती के अंदर हार्ट के पीछे स्थित और हार्ट से चिपके हुए 1.5 किलोग्राम के ट्यूमर (कैंसर) का सफल ऑपरेशन करके बच्ची को नई जिंदगी दी गई। मेडिकल भाषा में इस ट्यूमर को गैन्गिलयो न्यूरोफाइब्रोमा ऑफ लेफ्ट हीमोथोरेक्स कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे पोस्टीरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर कहा जाता है।

रायगढ़ के टुडरी गांव में रहने वाले परिवार की बच्ची जन्म के बाद पूरी तरह सामान्य थी परंतु 2 साल की उम्र होते-होते उसके चलने की क्षमता समाप्त हो गई। बच्ची अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब उन्होंने उड़ीसा के बुरला मेडिकल कॉलेज में दिखाया परंतु वहां बीमारी का पता नहीं चला। उसके बाद वे रायपुर एम्स में दिखाये जहां पर बीमारी का पता चला। इसमें बच्ची के स्पाइनल कॉड (रीढ़ की हड्डी) में ट्यूमर था। जिसके कारण बच्ची के पैरों की ताकत समाप्त हो गई थी। एम्स के न्यूरोसर्जन ने मासूम के स्पाइनल कॉर्ड से ट्यूमर निकाल दिया जिससे थोड़ा बहुत बच्ची चलने लगी परंतु कुछ ही समय बाद यह ट्यूमर पूरे बायीं छाती में फैल गया और यह ट्यूमर इतना बड़ा

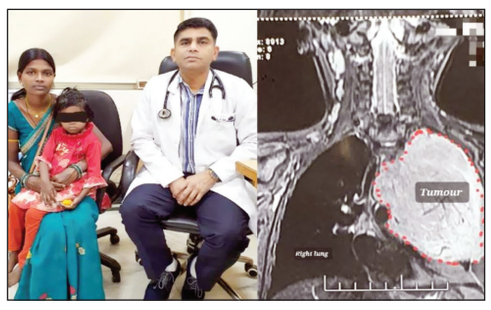

था जिससे बच्ची ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी।

एम्स के डॉक्टरों ने ट्यूमर के फैलाव को देखते हुए यह केस अम्बेडकर अस्पताल के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जन डॉ। कृष्णकांत साहू के पास रेफर कर दिया। डॉ। साहू बताते हैं कि यह ट्यूमर इतना बड़ा था कि शरीर के मुख्य अंग जैसे महाधमनी, सबक्लेवियन आर्टरी, हार्ट की झिल्ली एवं लंग हाइलम् को चपेट में ले लिया था जिसके कारण इसको निकालना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। डॉ। साहू बताते हैं कि उन्होंने फेफड़े और छाती के कैंसर के 250 से भी ज्यादा केस ऑपरेट कर चुके हैं। साथ ही पोस्टेरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर के 25 से भी ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं परंतु अभी तक 3 साल की बच्ची में इतना बड़ा पोस्टेरियर मेडिस्टाइनल ट्यूमर का केस पहली बार देखा। पहले तो ऑपरेशन के लिए मना कर दिया कि यह केस ऑपरेशन के लायक नहीं है क्योंकि इसमें बच्चे के जान जाने की 90 से 95 प्रतिशत संभावना है और ऑपरेशन नहीं भी करवाते तो कैंसर बीमारी के कारण 100 प्रतिशत जान जाने की संभावना है। फिर भी 5 प्रतिशत सफलता की आशा के साथ बच्ची के माता-पिता ऑपरेशन के लिए राजी हो गए।

इस ऑपरेशन को पहले एसीआई के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग में करने के लिए प्लान किया गया था। परंतु ट्यूमर के बहुत बड़े होने और मासूम की उम्र बहुत ही कम होने तथा हाई रिस्क केस होने के कारण यहां के एनेस्थीसिया विशेषज्ञों ने डीकेएस हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के ऑपरेशन थियेटर में ऑपरेशन की सलाह दी। डी। के। एस। सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक सर्जरी की एचओडी डॉ। शिप्रा शर्मा और डॉ। नितिन शर्मा से बात करके बच्चे को डीकेएस शिफ्ट कराया गया।

प्रदेश में 4 दिसम्बर तक मनाया जाएगा पुरूष नसबंदी पखवाड़ा

रायपुर। परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 21 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक पुरूष नसबंदी पखवाड़ा चलाया जाएगा। इस दौरान ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक विशेष अभियान चलाकर पुरूष नसबंदी के प्रति फैली अज्ञानता व भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। पखवाड़े के दौरान ए.एन.एम. और मितानिनें घर-घर जाकर चिन्हांकित हितग्राहियों को परिवार नियोजन के स्थाई व अस्थाई साधनों के बारे बताएंगी। हितग्राहियों को जरूरी परामर्श और परिवार नियोजन की सेवाएं भी इस दौरान प्रदान की जाएंगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परिवार कल्याण के उप संचालक डॉ. टी.के. टोंडर ने बताया कि देश की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। इसके लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में दो लाख 59 हजार 985 महिलाओं और 26 हजार 510 पुरूषों की नसबंदी की गई है। वर्ष 2017-18 में 53 हजार 236 महिलाओं एवं 7119 पुरुषों, 2018-19 में 61 हजार 342 महिलाओं एवं 5361 पुरुषों, 2019-20 में 59 हजार 991 महिलाओं एवं 6775 पुरुषों, 2020-21 में 28 हजार 159 महिलाओं एवं 2826 पुरुषों, 2021-22 में 57 हजार 257 महिलाओं एवं 4429 पुरुषों व 2022-23 में 80 हजार 704 महिलाओं एवं 6216 पुरुषों का नसबंदी ऑपरेशन किया गया है। सभी शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन के साधन निःशुल्क उपलब्ध हैं। इनमें पुरूष एवं महिला नसबंदी, निरोध, गर्भ निरोधक गोली, इंजेक्शन, कॉपर-टी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। परिवार नियोजन के लिए आवश्यक है

कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच तीन साल का अंतराल हो।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उपायों पर डॉ. टोंडर ने बताया कि सभी जिला चिकित्सालयों, चिन्हांकित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में एन.एस.व्ही. की सुविधा उपलब्ध है। पुरूष नसबंदी उन दंपत्तियों के लिए परिवार नियोजन का सबसे आसान उपाय है जिन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। एन.एस.व्ही. बिना चीरा व टांके के दस से 20 मिनट में पूरी की जाती है, और इस प्रक्रिया में दर्द नहीं होता। नसबंदी के बाद किसी भी प्रकार की शारीरिक दुर्बलता नहीं होती, बल्कि पहले जैसा ही भारी काम कर सकते हैं। शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों में नसबंदी के बाद पुरूष हितग्राहियों को तीन हजार रुपए और महिला हितग्राहियों को दो हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। यह महिला नसबंदी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और सरल है। पखवाड़ा के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले योग्य दंपति को गर्भनिरोधक के संबंध में परामर्श देते हुए इच्छित गर्भ निरोधक साधन या सेवा इच्छानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

आलाकमान करेगा सीएम का फैसला: दीपक बैज

■ राहुल गांधी को चुनाव आयोग के नोटिस पर बैज ने किया बचाव

रायपुर। चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर में कहा कि हम विधानसभा चुनावों में जीत रहे हैं। बैज ने दावा किया कि जनता ने विकास के नाम पर इस बार वोट दिया है। छत्तीसगढ़ में कही भी बदलाव की सुगबुगाहट नहीं है, बीजेपी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। बैज ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में जो भी विधायक दल का फैसला होगा उससे आलाकमान को बता दिया

जाएगा। आलाकमान ही फैसला करेगा की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा।

राहुल गांधी को चुनाव आयोग से मिले नोटिस पर दीपक बैज ने कहा कि भाषा की गरिमा का ध्यान बीजेपी को रखना चाहिए। बीजेपी ने 14 से 15 लोगों की फौज लगा रखी है जो कांग्रेस और उसके नेताओं को लेकर मर्यादाहीन बातें करती है। कांग्रेस ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करती है जो दूसरों के लिए अपमानजनक हो। बैज ने कहा कि जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस नेता को मूर्खों का सरदार करते हैं उसपर भी आपत्ति लेनी चाहिए, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम और उस पद को शोभा नहीं देता है।

बैज ने दावा किया की हम राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत रहे हैं। तेलंगाना को लेकर दीपक बैज ने बोला कि वहां कांग्रेस अच्छा फाइट कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस को लेकर वोटरों में खासा उत्साह है, वोटर इस बार बीआरएस को हटाकर कांग्रेस को मौका देने के पक्ष में हैं। बैज ने कहा कि जीत के बाद हम फिर से धान खरीदी का काम तय कीमत पर जारी रहेगा। कांग्रेस ने अपने गारंटी में जो भी वादे जनता से किए थे उन सभी वादों को हम हर कीमत पर पूरा करेंगे।

राजस्थान के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव के रण में भूपेश बघेल, करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के पक्ष में जमकर प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार अभियान में डटी हुई है। आज भी उनकी तेलंगाना में कई सभाएं है। पीएम मोदी भी आज से तेलंगाना दौरा कर कई सभाओं को संबोधित करेंगे। राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले 23 नवंबर तक सीएम भूपेश बघेल ने राजस्थान के अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार और रोड शो किया और कांग्रेस को जिताने की अपील राजस्थान की जनता से की। शनिवार से छत्तीसगढ़ सीएम तेलंगाना में प्रचार में शामिल होंगे। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। सीएम भूपेश बघेल ने राजस्थान में भाजपा के लगे होर्डिंग पर तंज कसा। दरअसर राजस्थान में भाजपा ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलने की होर्डिंग लगाई है। इसे लेकर भूपेश ने कहा कि प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, फिर वह राज्यों की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकता है? मोदी जी की गलत नीतियों के कारण देशवासी महंगाई से त्रस्त हैं यह तो उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है। अगर मोदी की गारंटी है तो पूरे देश में 450 में सिलेंडर दे दीजिए, जनता को केंद्र सरकार के प्रकोप से कुछ तो राहत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने केन्द्रीय मंत्री को लिखा पत्र

एयरपोर्ट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग

रायपुर। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया को रायपुर एयरपोर्ट में चल रही पार्किंग की अवैध वसूली को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। समिति ने कहा है कि पार्किंग की अवैध वसूली के चलते आम जनता में व्यापक रोष है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। जन आक्रोश इतना है कि आये दिन प्रताड़ितों द्वारा ट्वीटर पर रायपुर एयरपोर्ट पर अवैध वसूली को लेकर ट्वीट किये जाते है, एयरपोर्ट अथॉरिटी रायपुर के हेंडल पर टेग किया जाता है, पर एयरपोर्ट डायरेक्टर अवैध वसूली नहीं रुकवा पाते हैं। आज तक शो कॉज नोटिस और छोटी सी पेनल्टी लगाने के

अलावा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई जिससे अवैध वसूली रुक सके।

समिति ने पत्र में लिखा है कि निजी कार और एसयूवी के लिए 30 मिनट तक का पार्किंग शुल्क रुपए 20 निश्चित है, 30 मिनट से 2 घंटा तक के लिए यह पार्किंग शुल्क 35 रुपए निर्धारित है परंतु 30 मिनट से कम की पार्किंग में भी रुपए 50 की वसूली रंगदारी के साथ की जाती है। ठेकेदार ने बताया कि रायपुर मे लोगों ने कमर्शियल वाहनों का निजी नंबर ले रखा है इस लिए सबसे वसूलता है रु 50/। समिति ने पत्र में बताया कि एयरपोर्ट डायरेक्टर ने एक शिकायतकर्ता को बताया है कि कमर्शियल वाहन से पार्किंग के रु 20 के अतिरिक्त रु 30 अतिरिक्त लिए जाते है और ठेकेदार ने उन्हें बताया है कि आरटीओ से ठेकेदार ने बात की और उसे (ठेकेदार को) बताया गया कि यहाँ (रायपुर में) लोगों ने कमर्शियल गाडी का भी प्राइवेट नंबर लिया हुआ है, इस लिए ठेकेदार रु 50 की वसूली सभी वाहनों से करता है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने स्वीकार किया कि उन्होंने भी इस प्रकार की रु 50 की वसूली को देखा है और उन्होंने इस कारण से ठेकेदार का चालान भी काटा है। समिति ने आरोप लगाया कि सब कुछ जानने के बाद भी एयरपोर्ट डायरेक्टर इस अवैध वसूली को रुकवा नहीं सके जो कि उनको प्रशसनिक रूप से असक्षम प्रमाणित करता है।

फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना की दस्तक, कहीं महामारी के विकराल रूप का आगाज तो नहीं!

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। दरअसल, पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले थम गए थे। कई दिनों से कोरोना के एक भी केस नहीं मिल रहे थे। लेकिन गुरुवार को कोरोना के एक केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि शुक्रवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इस बीच चीन में एक नई बीमारी पनप रही है। रहस्यमय निमोनिया की चपेट में चीन आ गया है। इस नई महामारी ने पूरे विश्व को एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। यही कारण है कि फिर से कोरोना के केस बढ़ने से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है।

छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1 है। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 1173507 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कुल मृतकों की संख्या 14190 है।

कोरोना से पीड़ित मरीज को सर्दी खासी के साथ ही बुखार की शिकायत होती है। इस बीमारी में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इन्फेक्शन आसानी से फैल जाता है। इसके साथ ही मरीज को काफी कमजोरी होती है। इम्युनिटी कम होने पर मरीज की

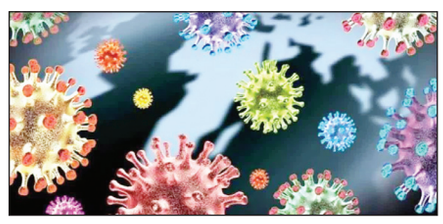

मौत हो जाती है। यही कारण है कि पूरे विश्व में कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है।

साल 2019 में चीन के वुहान शहर से निकली कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मौत का तांडव मचा रखा था। कोरोना से हर दिन सैकड़ों लोगों की मौत हो रही थी। 2019 के दिसंबर माह में चीन में इस महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके बाद अन्य देशों में भी इसके मामले सामने आने लगा। भारत में भी 2020 के जनवरी माह के बाद से महामारी ने दस्तक दे दी थी। अस्पतालों कोरोना से मरने वालों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही थी। हर दिन बढ़ते मामलों के बाद पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था। हर देश में कोरोना के कारण देशबंदी जैसे हालात थे। इसके कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी।

डिजिटल इंडिया मिशन का चुनावी फायदा

अतुल सिन्हा

चुनाव के इस माहौल में प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सभाओं और कार्यक्रमों के दौरान उनका डिजिटल इंडिया मिशन खासा काम आ रहा है। हाल ही में झारखंड के आदिवासियों के बीच पहुंचे मोदी के कार्यक्रमों और जनजाति गौरव यात्रा के दौरान भी उनके इस मिशन का फायदा नज़र आया। अपनी सरकार की दो पारियों की उपलब्धियां गिनाते हुए मोदी के लिए इन यात्राओं में जो मजबूत जनाधार दिख रहा है, वह है ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के उन ग्रामीण उद्यमियों का, जिनकी संख्या अब बीस लाख से भी ज्यादा हो गई है। देशभर में करीब साढ़े पांच लाख सीएससी चल रहे हैं और हरेक सीएससी से कई लोग जुड़े हैं। इन केंद्रों का मकसद खासकर देश के तमाम गांवों में लोगों को ई-गवर्नेंस की सुविधा देकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सामान्य सेवा केंद्रों (ष्टस्ष्ट) का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। अगर सरकारी दावे की बात करें, तो संसद में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2022 की फरवरी तक देशभर में 4,63,705 सीएससी काम कर रहे हैं, जिनमें करीब 15 लाख लोग काम करते हैं। देश के करीब ढाई लाख ग्राम पंचायतों में से ज्यादातर ग्राम पंचायतें इस सेवा से जुड़ी हैं और इन्हें ग्राम स्तरीय उद्यमी यानी वीएलई चलाते हैं। आम तौर पर देश में लाखों ऐसे लोग हैं, जिन्हें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति या आवास प्रमाण पत्र जैसे तमाम दस्तावेजों के लिया भटकना पड़ता है। वैसे तो तमाम शहरों में ऐसे कई केंद्र आपको मिल जाएंगे जो मोटी रकम लेकर ये दस्तावेज़ बनवाने का काम करते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर सीएससी यह काम करता है और इसके जरिये लोगों को मुफ्त में ये सारी सुविधाएं देता है। और अब तो सरकारी तौर पर मुफ्त कानूनी सहायता देने का काम भी इसके जरिये किया जा रहा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के मुताबिक न्याय विभाग और सीएससी-एसपीवी की ओर से चलाई जा रही टेली लॉ सेवा के तहत अबतक 59 लाख से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह का लाभ मिला है। अगर आप दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जाएंगे, तो वहां एमएसएमई के स्टॉल में आपको सीएससी के वालंटियर्स मिल जाएंगे। उनके मुताबिक इस कार्यक्रम से उन्हें काफी लाभ मिला है और यह मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। उनका कहना है कि वैसे तो इस योजना की शुरुआत कांग्रेस की सरकार के दौरान 2009 में ही हुई थी, लेकिन 2015 में सीएससी 2.0 के बाद डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इसमें ज़बरदस्त तेजी आई और इसका गांव-गांव में विस्तार हुआ।

प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित शब्द

ललित गर्ग

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ की गयी 'पनौती' (अपशकुन), जेबकतरा एवं कर्ज माफी जैसी अशोभनीय टिप्पणियों के कारण निशाने पर हैं। चुनाव आयोग (ईसी) ने हालिया टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करके निर्णायक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा चुनाव आयोग में दर्ज की गई एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए की गयी है। चुनाव आयोग ने जहां पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा पर चिंता व्यक्त की वही भाजपा ने तर्क दिया कि ऐसी भाषा एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता के लिए 'अशोभनीय' है। पिछले लम्बे दौर से विश्वनेता के रूप में प्रतिष्ठित देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दर्शन, उनके व्यक्तित्व, उनकी बढ़ती ख्याति, उनकी बहुआयामी योजनाओं व उनकी कार्य-पद्धतियों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में विपक्षी नेताओं और विशेषत: कांग्रेस नेताओं ने अमर्यादित, अशिष्ट, छिछालेदार भाषा का उपयोग कर राजनीतिक मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है। विडम्बना देखिये कि मोदी को गालियां देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करने वाले राहुल गांधी इसका खामियाजा भी भुगतते रहे हैं, लेकिन राजनीतिक अपरिवक्वता के कारण वे कोई सबक लेने का तैयार नहीं है।

निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता नेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ असत्यापित आरोप लगाने से रोकती है। लेकिन राहुल गांधी ने राजस्थान में हाल की रैलियों में प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उनके लिए 'पनौती', जेबकतरे और अन्य विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी के ये अशोभनीय एवं मर्यादाहीन बयान क्या रंग लायेगा, यह भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन स्वस्थ एवं आदर्श लोकतंत्र के लिये देश के प्रधानमंत्री के लिये इस तरह के निम्न, स्तरहीन एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग होना, एक विडम्बना है, एक त्रासदी है, एक शर्मनाक स्थिति है। केवल कांग्रेस ही नहीं, अन्य राजनीतिक दल के नेता भी ऐसी अपरिपक्वता एवं अशालीनता का परिचय देते रहे हैं। पिछले नौ वर्षों में उद्योगपतियों को चौदह लाख करोड़ रुपये की छूट देने के आरोप भी सत्यता से परे, तथ्यहीन, भ्रामक एवं गुमराह करने वाले हैं। 'जेबकतरे' शब्द का प्रयोग करते हुए आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री लोगों का ध्यान भटकाते हैं। जबकि उद्योगपति गौतम अडानी उनकी (लोगों की) जेब से पैसे निकालते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जेबकतरे इसी तरह काम करते हैं। आयोग ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में भी बताया जिसमें कहा गया था कि अगर संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है तो प्रतिष्ठा के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 में संरक्षित जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। इन दो अधिकारों को संतुलित करना एक संवैधानिक आवश्यकता है। लेकिन राहुल गांधी को यह संतुलन साधना कहा आता है?

राहुल गांधी ने अहमदाबाद में विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद राजस्थान में चुनावी भाषण में मोदी के खिलाफ 'पनौती' जैसे आपत्तिजनक, विवादित एवं अपशब्द का इस्तेमाल किया था। यह एक शब्दभर नहीं है, बल्कि अनेक कुटिलताओं की अभिव्यक्ति है, 'पनौती' मोटे तौर पर ऐसे शख्स के लिये उपयोग किया जाता है, जिसकी मौजूदगी होने भर से बनता काम बिगड़ जाता है। आम तौर पर पनौती शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इंगित किया जाता है जो बुरी किस्मत लाता है। वैसे इसका किसी ज्ञान-विज्ञान और तर्क से नाता नहीं है। जाने-माने भाषाविद् डॉक्टर सुरेश पंत के मुताबिक, हिंदी में -औती प्रत्यय से अनेक शब्द बनते हैं। इनमें कटौती, चुनौती, मनौती, बपौती इत्यादि शामिल हैं। पनौती शब्द नकारात्मकता एवं अशुभता का सूचक है। पनौती को शनि की बुरी दशा का समय माना जाता है। इसका मतलब बाढ़ भी होता है। पनौती तमिल शब्द पन्नादाई का अपभ्रंश भी है। इसका मतलब होता है 'एक ढीला बुना हुआ कपड़ा' या 'मूर्ख'।

बात केवल राहुल गांधी की ही नहीं है, कौन भूल सकता है सोनिया गांधी का वह बयान, जिसने वास्तव में गुजरात की जनता को झकझोर कर रख दिया था। तब सोनिया ने गुजरात के तत्कालीन और बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मौत का सौदागर' बताया था। सोनिया ने कहा था, मेरा पूरा भरोसा है कि आप ऐसे लोगों को मंजूर नहीं करेंगे जो जहर के बीज बोते हैं। 'मौत का सौदागर' के बाद 'जहर की खेती' के इस बयान ने गुजरात ही नहीं, देश की जनता की भावना को जगा दिया। नतीजा लोकसभा चुनाव के परिणाम के रूप में सामने आया, जिसमें बीजेपी को 278 और कांग्रेस को 45 सीटें मिलीं। जनता को बेवकूफ एवं नासमझ समझने की भूल कांग्रेस बार-बार करती रही है और बार-बार मात खाती रही है। इन चुनावों में भी ऐसी मात खाने को मिले तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि जनता अपने सर्वोच्च नेतृत्व को मर्यादाहीन तो कत्तई नहीं देखना चाहती। कभी पूर्व कैबिनेट मंत्री मणिशंकर अय्यर मोदी को 'नीच' तक कह देते हैं तो राहुल तो सर्जिकल स्ट्राइक पर 'खून की दलाली' जैसे आरोप लगाते रहे हैं।

नोटबंदी को लेकर जहां पूरा देश नरेन्द्र मोदी के साथ खड़ा था, तब विपक्ष को काले कारोबारियों के साथ खड़ा होने में जरा भी शर्म नहीं आई। विपक्ष ने दुनिया के कुख्यात रहे तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी, कर्नल गद्दाफी से प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर डाली। इस तरह के स्तरहीन, ओछे एवं अमर्यादित बयानों से न केवल विपक्ष दलों के नेताओं बल्कि कांग्रेस पार्टी की न केवल फजीहत होती रही है, बल्कि उसकी बौखलाहट को दर्शाती रही है। इस तरह के लोग राजनीति में जगह बनाने के लिये ऐसी अनुशासनहीनता एवं अशिष्टता करते हैं। राहुल के इस तरह के ओछे, स्तरहीन एवं अशालीन शब्दों के प्रयोग का एक लम्बा सिलसिला है। मोदी पर गाली की बौछार में कभी उनको सांप, बिच्छू और गंदा आदमी कहा गया था। तो कभी लहू पुरुष, पानी पुरुष और असत्य का सौदागर भी बताया। सत्ता के शीर्ष पर बैठकर यदि इस तरह जनतंत्र के आदर्शों को भुला दिया जाता है तो वहां लोकतंत्र के आदर्शों की रक्षा नहीं हो सकती। राजनैतिक लोगों से महात्मा बनने की आशा नहीं की जा सकती, पर वे अशालीनता एवं अमर्यादा पर उतर आये, यह ठीक नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरा ईश्वर दरिद्र-नारायणों में रहता है।' आज यदि उनके भक्तों-कांग्रेसजनों से यही प्रश्न पूछा जाये तो संभवत: यही उत्तर मिलेगा कि हमारा ईश्वर कुर्सी में रहता है, सत्ता में रहता है। तभी उनमें अच्छाई-बुराई न दिखाई देकर केवल सत्तालोलुपता दिखती है।

ये तथाकथित नेता गाली ही नहीं देते रहे, बल्कि गोली तक की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन कोई गाली या गोली मोदी का बाल भी बांका नहीं कर सकेंगी क्योंकि वे जनसमर्थन से इन ऊंचाइयों को पाया है। मोदी को तो बोटी-बोटी काट देने की धमकी खुलेआम दी गयी। किसी ने मोदी को रैबिज से पीड़ित बताया तो किसी ने उन्हें केवल चूहे मात्र माना। चायवाले से तो वे चर्चित हैं। लेकिन मोदी के व्यक्तित्व की ऊंचाई एवं गहराई है कि उन्होंने अपने विरोध को सदैव विनोद माना। मोदी को बार-बार कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है। चुनाव का समय हो या सामान्य कार्य के दिवस मोदी ने कम गालियां नहीं खाईं। उनके विचारों को, कार्यक्रमों को, देश के लिये कुछ नया करने के संकल्प को बार-बार मारा जा रहा है। लेकिन मोदी भारत की आजादी के बाद बनी सरकारों के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कोई गोली या गाली नहीं मार सकती। क्योंकि मोदी की राजनीति व धर्म का आधार सत्ता नहीं, सेवा है, राष्ट्र-निर्माण है। जनता को भयमुक्त व वास्तविक आजादी दिलाना उनका लक्ष्य है। वे सम्पूर्ण भारतीयता की अमर धरोहर हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन, कालेधन पर शिकंजा कसने, वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने, नया भारत निर्मित करने, स्वच्छता अभियान, दुनिया की सशक्त तीसरी आर्थिक ताकत बनाने, दलितों के उद्धार और उनकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। उनके जीवन की विशेषता कथनी और करनी में अंतर नहीं होना है। चुनावी बिसात बिछते ही या फिर वर्तमान राजनीति में जिस प्रकार से भाषा की मर्यादाएं टूट रही हैं और हमारे राजनेताओं का जो आचरण सामने आ रहा है, उसे कहीं से भी हमारे लोकतंत्र, राजनीति, सभ्य समाज या हमारी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श स्थिति नहीं कहा जा सकता।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागकुण्डल्युपनिषद् (भाग-9)

गतांक से आगे...

तीन वर्ष तक इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा का प्रवेश ब्रह्म द्वार में हो जाता है। जिह्वा के वहाँ प्रवेश कर जाने पर विधिवत् उसके द्वारा मंथन करना चाहिए। ऐसे कई योग्य साधक होते हैं, जो मंथन के बिना ही खेचरी सिद्ध कर लेते हैं, परन्तु जिन्होंने खेचरी मंत्र सिद्ध कर लिया है, वे ही मन्थन के बिना सिद्ध कर पाते हैं (अन्य नहीं)।

जप और मंथन दोनों करने से जल्दी लाभ मिलता है। मंथन हेतु लोहा, चाँदी या स्वर्ण की शलाका के एक सिरे पर दुग्ध लगा हुआ तन्तु लगाए, पुन: उसे नाक में डाल कर सुखासन में बैठ कर प्राण को हृदय में निरोध करके नेत्रों से भौंहों के मध्य देखते हुए उसी शलाका से मंथन करे। इस प्रकार छ: मास तक मंथन करने पर इसका प्रभाव दिखलाई देने लगता है। उस समय साधक की अवस्था सोते हुए बालक की तरह होती है। इस मन्थन को मास में एक बार करे, नित्य न करे। जिह्वा को भी ब्रह्मरन्ध्र में बार-बार प्रविष्ट करे। द्वादश वर्ष तक इसी तरह अभ्यास करने से सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है।

अभ्यास की इस अवस्था में योगी अपने अन्तर में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है; क्योंकि जिह्वा के ब्रह्म विवर में जाने वाले मार्ग में ही ब्रह्माण्ड की स्थिति है।

ब्रह्माजी ने कहा। खेचरी का- - मेलन मंत्र ह्रीं भंसं मं पंसं क्षं है। हे शंकर जी ! कृपा करके आप हमें यह बतायें कि साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या अभिप्राय है?

(आत्मदर्शन के समय साधक की दृष्टि का वर्णन) आत्मानुसंधान की साधना के प्रथम चरण में साधक की दृष्टि एवं स्थिति प्रकाशरहित अमावस्या की द्वितीय चरण में प्रतिपदा (अल्प प्रकाश की) तथा तृतीय चरण में पूर्णिमा (पूर्ण प्रकाश) की होती है। वही कल्याण की स्थिति है। जब मनुष्य कामनाबद्ध होकर विषयों की ओर दौड़ता है, उस समय विषयों को प्राप्त करते हुए कामनाएँ बढ़ती जाती हैं। इसलिए विषय और कामना दोनों से अलग होकर (आत्मा में ध्यान लगाते हुए) ही विशुद्ध परमात्मभाव की प्राप्ति की जा सकती है। अपना हित चाहने वाले को समस्त मिथ्या विषयों को छोड़कर शक्ति (कुण्डलिनी) के मध्य में मन को स्थिर करके उसी में स्थिर रहना चाहिए।

[मन को चेतन सत्ता शक्ति के मध्य स्थिर करना स्व का चेतन में वास कहा जाता है। जब चेतन में वास होता है, तो शरीर को किन्हीं लौकिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तक शक्ति में वास (पूरी तरह स्थिर होना) न सधे, तब तक यत्नपूर्वक उपवास चेतना में आंशिक रूप से रहने का अभ्यास करना चाहिए। उपवास की स्थिति में शरीर के लिए न्यूनतम आहार देकर भी उसे सक्रिय और संतुष्ट रखा जा सकता है। उपवास साधना को शक्ति में वास की साधना का पूर्वाभ्यास कहा जा सकता है।] मन से मन को देखते हुए उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करके उनसे मुक्त होने को ही परम पद कहा गया है। मन ही बिन्दु (ईश्वर) है और वही (जगत्प्रपंच) की उत्पत्ति एवं स्थिति का मुख्य कारण है।

क्रमश: ...

राष्ट्रीय संविधान दिवस

श्वेता गोयल

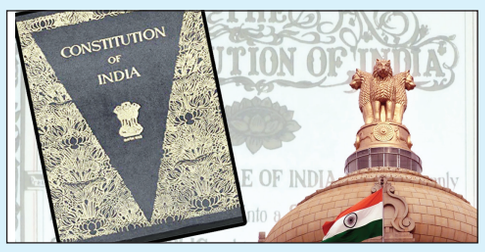

26 नवम्बर को देश में प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। हालांकि वैसे तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था लेकिन इसे स्वीकृत 26 नवम्बर 1949 को ही कर लिया गया था। डा. भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण ही भारत का संविधान ऐसे रूप में सामने आया, जिसे दुनिया के कई अन्य देशों ने भी अपनाया। वर्ष 2015 में डा. अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष में पहली बार देश में 26 नवम्बर को संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इस साल हम 74वां संविधान दिवस मना रहे हैं। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।

संविधान प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिनों तक चली थी और संविधान के निर्माण में करीब तीन वर्ष का समय लगा था। संविधान के निर्माण कार्य पर करीब 64 लाख रुपये खर्च हुए थे और इसके निर्माण कार्य में कुल 7635 सूचनाओं पर चर्चा की गई थी। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन 44वें संविधान संशोधन के जरिये सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया, जिसके बाद भारतीय नागरिकों को छह मूल अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28), संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30) तथा संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 32) शामिल हैं। संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का वर्णन है और संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इनमें संशोधन भी हो सकता है तथा राष्ट्रीय आपात के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है।

भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्यों पर नजर डालें तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी रोचक बात यही है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सर्वप्रथम सन् 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए लेकिन भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा ठुकरा दिया गया था। 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मांग की कि भारत का राजनैतिक भाग्य भारतीय स्वयं बनाएंगे लेकिन अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के गठन की लगातार उठती मांग को ठुकराया जाता रहा। आखिरकार 1939 में कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव में कहा गया कि स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ही एकमात्र उपाय है और सन् 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जो भारत का संविधान तैयार करेगी। सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा पहली बार समवेत हुई किन्तु अलग पाकिस्तान बनाने की मांग को लेकर मुस्लिम लीग द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया। दो दिन बाद संविधान सभा की बैठक में डा. राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और वे संविधान बनाने का कार्य पूरा होने तक इस पद पर आसीन रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ और संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली 'संविधान निर्मात्री समिति' का गठन किया गया, सर्वसम्मति से जिसके अध्यक्ष बने भारतीय संविधान के जनक डा. भीमराव अम्बेडकर। संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए संविधान में पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की गई है, जिससे भारतीय संविधान का सार, उसकी अपेक्षाएं, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। प्रस्तावना के अनुसार, "हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" संविधान की यह प्रस्तावना ही पूरे संविधान के मुख्य उद्देश्य को प्रदर्शित करती है।

लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच फंसा नेपाल

आदिति फडणीस

नेपाल में क्या दोबारा राजशाही का दौर लौट सकता है? इस सवाल पर पोखरा के कारोबारी बुद्धिमान गुरुंग जोर देकर कहते हैं, 'कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा।' गैस बॉटलिंग कंपनी के प्रवर्तक गुरुंग के नेपाल में रियल एस्टेट के साथ-साथ कई अन्य तरह के कारोबार चल रहे हैं। उन्होंने कई साल तक नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर स्थानीय चुनाव लड़े हैं। नेपाली कांग्रेस वह प्रमुख पार्टी है, जो नेपाल में राजशाही का खुलकर विरोध करती रही है। नेपाल में 2008 तक राजशाही रही। अंतिम राजा शाह वंश के ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह को संवैधानिक तरीके से गद्दी से हटाकर नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश बन गया। तब से लेकर अब तक आम लोगों में राज परिवार के प्रति यदा-कदा प्रेम उभर आता है। राज परिवार ने भी यह जाहिर किया है कि वह दोबारा सत्ता संभालने में सक्षम है।

इस साल फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र पूर्वी नेपाल के झापा स्थित काकरभित्ता में विशाल समारोह में शामिल हुए थे। यह शानदार समारोह पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के नेतृत्व वाली नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी- एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी से निकाले गए नेता दुर्गा परसाई ने आयोजित किया था। परसाई कारोबारी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं जो नेपाल के सरकारी बैंकों से पैसा लेकर नहीं लौटाने के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। परसाई के कई रूप देखने को मिलेंगे और शायद अपने राजनीतिक करियर को उड़ान देने के लिए उन्होंने पूर्व राजा की आड़ में व्यापक अभियान शुरू किया है। लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए उन्होंने धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, संस्कृति और नागरिक बचाओ का नारा बुलंद किया है। कई बड़ी-बड़ी हस्तियां इस समारोह में आई थीं।

राजा ने भी अपने पूरे परिवार के साथ इसमें शिरकत की, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया। इस मौके पर परसाई ने कहा कि हम कभी लोकतंत्र के हिमायती नहीं थे और ऐसा लोकतंत्र तो बिल्कुल नहीं चाहते, जो एक करोड़ युवा नेपालियों को खाड़ी देशों में भेजता है। मई में राजा ज्ञानेंद्र ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था जो इस साल का दूसरा था। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के प्रमुख हैं और इस पीठ के नेपाल की राजशाही से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कई बार राजा से मिल चुके हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (नैशनल लोकतांत्रिक पार्टी अथवा आरपीपी) को राज परिवार समर्थक दल माना जाता है। वर्ष 2013 से इस दल का प्रमुख राजनीतिक एजेंडा नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना और यहां राजशाही की वापसी रहा है।

नेपाल में किसी को भी इसमें कोई शक नहीं है कि नैशनल लोकतांत्रिक पार्टी का मुख्य उद्देश्य राजशाही को पुन: स्थापित करना है। इस पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगडेन को एक संतुलित नेता माना जाता है। वह कहते हैं कि नैतिक मूल्यों, स्थायित्व और बेहतर व्यवस्था के लिए धार्मिक मूल्यों पर आधारित समाज के प्रति जनता का सहज समर्थन है। स्थायित्व बहुत ही प्रभावशाली शब्द है। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कुछ सप्ताह पहले बिराटनगर की एक रैली में पूरे पांच साल तक देश के प्रधानमंत्री बने रहने की बात करते हुए चर्चाओं को हवा दे दी थी। कुल 275 सदस्यों वाले सदन में सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस और कुछ अन्य छोटे दलों के साथ किसी तरह संतुलन बनाकर सरकार चला रहे प्रचंड की पार्टी के 32 सांसद हैं। इन दलों के बीच बहुत ही जटिल किस्म का समझौता है। इसके तहत नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पांच साल के कार्यकाल में से ढाई साल वह भी इस पद पर रहेंगे।

सरकार में बने रहने के प्रति अनिश्चितता के बीच मंत्री अतिरिक्त समय देकर काम में जुटे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले चुनाव के लिए उनके पास पर्याप्त फंड है। यही वजह है कि नेपाल में घोटालों की इतनी भरमार हो गई है जो पहले कभी नहीं देखी गई। यही नहीं, चीन से सोना तस्करी, अमेरिका में शरण पाने के लिए अफसरशाहों और मंत्रियों की मिलीभगत से भूटानी शरणार्थियों के रूप में नेपाली लोगों की तस्करी, हार और कुंठा का भाव जैसी स्थितियां उभर रही हैं, जो नेपाल में पहले कभी नहीं रहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद दहल ने इस साल जून में भारत की यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने साथ के पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के वादे के बजाय भारत से ठोस निवेश प्रस्ताव ले जाना उनकी प्राथमिकता है। उस समय भारत को 679 मेगावॉट लोअर अरुण और 480 मेगावॉट फुकत करनाली पनबिजली जैसी परियोजनाओं के विकास का ठेका मिला था। लेकिन, चीन द्वारा निर्मित पोखरा और भैरहवा एयरपोर्ट को अभी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में मान्यता मिलना बाकी है, क्योंकि वहां भारतीय उड़ानों के संचालन के लिए भारत और नेपाल के बीच 2009 में हुए द्विपक्षीय विमानन समझौते पर फिर से काम करने की जरूरत है। चीन से पैसे उधार लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस किए गए पोखरा हवाईअड्डे पर अभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन नहीं हो रहा है। इस साल के शुरू में जब से यह हवाईअड्डा चालू हुआ है, केवल चीन से चार उड़ानें यहां उतरी हैं। इनमें दो पर्यटकों की चार्टर्ड फ्लाइट थीं और दो भूकंप प्रभावितों के लिए राहत सामग्री लेकर आए विमान। इस हवाईअड्डे के विकास के बदले नेपाल हर महीने अरबों रुपये ब्याज के रूप में चुका रहा है, लेकिन राजस्व की संभावना अभी दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती। हालांकि वह स्थिति अभी नहीं आई है जब रनवे पर बकरियां चरने लगेंगी। इन तमाम विषमताओं के बीच नेपाल कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जजारकोट भूकंप ने लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया, नेपाल के कई ग्रामीण इलाकों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। यही नहीं, लोग रोजमर्रा रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

आज का इतिहास

1966 फ्रांस की रेंस नदी के मुहाने पर विश्व के पहले ज्वारीय ऊर्जा संयत्र ने काम करना शुरू किया।

1967 लिस्बन में बादल फटने से करीब 450 लोग मरे।

1976 वार्सो संधि संगठन संयुक्त सचिवालय की स्थापना की गयी।

1977 एक वक्ता ने दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में प्रसारित इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन अनुरूपित सदर्न टेलीविज़न का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए दर्शकों को चेतावनी दी कि बुराई के अपने सभी हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए।

1983 लंदनहोट्री हवाई अड्डे पर ब्रिंकस-एमएटी के गोदाम में छह लुटेरों ने सेंध लगाई और तीन टन सोने के बुलियन चुराए, जिनमें से कई कभी बरामद नहीं हुए।

1990 ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन की महारानी को अपना इस्तीफा सौंपा।

2003 विश्व व्यापार संगठन द्वारा अनुचित तरीके से निर्धारित किए गए अमेरिकी स्टील निर्यात शुल्कों के खिलाफ जापानियों ने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी। जापान ने जिन कदमों पर योजना बनाई है, उनमें से एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में अमेरिकी डॉलर का शुल्क ले रहा है।

2006 गाजा पट्टी में इजरायल और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच संघर्ष विराम शुरू हुआ। इसने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बासंद इजरायल के प्रधान मंत्री एहुद ओलमर्ट के बीच वार्ता की।

2007 पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा की कि वह पाकिस्तानी आम चुनाव, 2008 में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हालांकि, वह पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के अधीन प्रधान मंत्री के रूप में काम नहीं करेंगे।

2008 पूरे मुंबई में शूटिंग और बमबारी हमलों का एक समन्वित समूह शुरू हुआ, अंत में कुल 173 लोगों की मौत हो गई और मोरेथन 300 अन्य घायल हो गए।

2011 अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो बलों ने अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के साथ दो पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को तैनात किया।

केसीआर खुलकर कर रहे वोट बैंक की राजनीति

नीरज कुमार दुबे

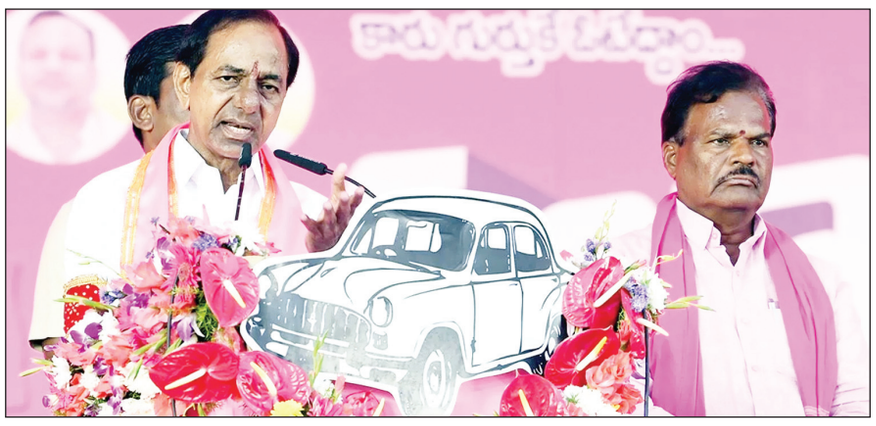

तेलंगाना में जैसे-जैसे मतदान का समय करीब आ रहा है वैसे-वैसे तुष्टिकरण की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। मुख्यमंत्री केसीआर और उनके करीबी असद्दुदीन ओवैसी खुलकर अपनी सभाओं में मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं दूसरी ओर कांग्रेस भी खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने में लगी हुई है। दस साल से तेलंगाना की सत्ता में जमे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यकों के लिए मात्र दो हजार करोड़ रुपए खर्च किये जबकि उनके नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति की सरकार ने दस साल में अल्पसंख्यकों के विकास पर 12 हजार करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च की। केसीआर अपनी सभाओं में उम्मीद जता रहे हैं कि अल्लाह ने चाहा तो तेलंगाना एक बार फिर उनके पास आयेगा।

केसीआर के भाषणों को आप सुनेंगे तो आपको आभास होगा कि वह किसी चुनावी रैली को नहीं बल्कि धार्मिक रैली को संबोधित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री केसीआर ने संविधान की शपथ लेते समय सबके साथ न्याय करने की बात कही थी लेकिन उनके भाषणों से लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। हम आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाने के लिए भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने यह दावा भी कर दिया है कि यदि उनकी सरकार तीसरी बार भी बनती है तो वह मुस्लिम युवाओं के लिए आईटी पार्क स्थापित करेंगे। यहां सवाल केसीआर से है कि क्या आईटी पार्क अब धर्म के आधार पर बनाये जाएंगे। क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते आने वाले समय में देश में पुल, पुलिया, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस व ट्रेन भी धार्मिक आधार पर चलेंगी? सवाल यह है कि आखिर किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने को आतुर नेता देश को किस राह पर ले जाना चाहते हैं? यदि राजनीतिक दल धर्म के आधार पर संसाधनों को स्थापित करने की बात करने लगेंगे तो उनमें और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई में क्या अंतर रह जायेगा जो 2047 तक भारत के इस्लामीकरण का लक्ष्य लेकर चल रही है?

कहीं यह केसीआर की ओर से दी जा रही शह का परिणाम तो नहीं है कि एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी खुलेआम पुलिस अधिकारियों को धमकी देने लगते हैं? कहीं यह केसीआर द्वारा दी जा रही शह का परिणाम तो नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस अधिकारी को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर वह (अपने समर्थकों को) इशारा करेंगे तो पुलिस अधिकारी वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे? इसके अलावा केसीआर अपनी सभाओं में भाजपा की हार की भविष्यवाणी करें इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन सवाल यह है कि वह आखिर मुस्लिमों से यह क्यों कह रहे हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2024 में भाजपा हारने वाली है? भाजपा 2024 में हारे या जीते लेकिन इससे किसी को डरने या नहीं डरने की जरूरत कहां से आ गयी? सबको पता होना चाहिए कि भारत में राजनीतिक पार्टियां या सत्ताधारी दल कानून से ऊपर नहीं हैं। हम आपको बता दें कि महेश्वरम से शिक्षा मंत्री सविता इंद्र रेड्डी की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केसीआर ने यह विवादित बयान दिया है।

केसीआर ने कहा कि हम पेंशन दे रहे हैं जो मुसलमानों को भी मिल रही है। हमने आवासीय विद्यालय खोले हैं जिनमें मुस्लिम विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। हम सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा, ''आज, हम मुस्लिम युवाओं के बारे में और हैदराबाद के पास उनके लिए एक विशेष आईटी पार्क स्थापित करने सोच रहे हैं। आईटी पार्क पहाड़ी शरीफ के पास बनेगा।'' प्रदेश के जहीराबाद में, केसीआर ने केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी किसी का कोई भला नहीं कर रही, ''देश का माहौल खराब कर रही है।'' उन्होंने कहा कि राजग सरकार का कार्यकाल केवल कुछ और दिनों तक चलेगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सत्तारुढ़ गठबंधन 2024 का लोकसभा चुनाव हार जाएगा। उन्होंने कहा, ''भाजपा देश में माहौल खराब कर रही है। इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। यह उनके लिए स्थायी कार्यकाल नहीं होगा। डरने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कार्यकाल बस कुछ और दिन ही है। वे हमेशा के लिये नहीं रहेंगे। जब लोगों को एहसास होगा तो वे उन्हें बाहर निकाल देंगे। फिर, यह खुशहाली वाला देश होगा।''

तेलंगाना में किसी तरह के कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं होने तथा राज्य को 'शांतिपूर्ण' बताते हुये राव ने कहा कि बीआरएस सरकार ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक विकास पर 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन के दौरान 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि जब तक केसीआर जीवित हैं, तेलंगाना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, अलग राज्य बनने के बाद तेलंगाना में विकास संभव हो सका है। उन्होंने लोगों से पूछा, ''तेलंगाना के लिए राज्य का दर्जा किसने हासिल किया। 24 घंटे मुफ्त बिजली लागू करने में कौन सक्षम है। हर घर नल का पानी किसने पहुंचाया।'' मौके पर मौजूद लोगों ने 'केसीआर-केसीआर' कहकर इसका जवाब दिया। महेश्वरम में रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों एवं हिंदुओं को दो आंखों की तरह मानती है और सभी को साथ लेकर चलती है।

तेलंगाना में भाजपा के बंडी संजय की प्रतिष्ठा पर दांव

जलज मिश्रा

यह वो जमीन है जहां से तेलंगाना बनाने के आंदोलन की चिंगारी फूटी थी। करीमनगर से मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर सांसद रह चुके हैं और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव भी इसी जिले के रहने वाले थे। उनका गृहनगर हुस्नाबाद में है। आंध्र प्रदेश अलग होने के बाद नए तेलंगाना में पुराने जिलों को बांटकर दस जिले से 33 जिले कर दिए गए। करीमनगर और उससे काटकर बनाए गए तीन अन्य जिलों की कुल 13 सीटों पर इस बार मुकाबला कुछ अलग है। भाजपा के बड़े चेहरे भी यहीं से मैदान में हैं। पिछले कुछ समय में कुछ सांप्रदायिक मुद्दों ने भी इस क्षेत्र की राजनीति को गरमा दिया था और अब इसका असर भी है। पिछले दिनों बीआरएस के गृह मंत्री महमूद अली ने मुख्यमंत्री केसीआर की समानता पैगंबर मोहम्मद के दौर के एक बादशाह से कर दी तो लोगों में नाराजगी हुई। हालांकि बाद में उन्होंने माफी भी मांग ली। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े चेहरे बंडी संजय करीमनगर सदर से मैदान में हैं। वह करीमनगर से सांसद हैं। वह विधायक का चुनाव पिछली बार भी हार गए थे। लेकिन भाजपा ने यहां खुद को लगातार मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी 27 नवंबर को करीमनगर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्थानीय निवासी गर्व से बताते हैं कि यहीं के एसआरके कॉलेज में केसीआर ने 2001 में अलग तेलंगाना राज्य के लिए पहली सभा की थी। करीमनगर के प्रवेश द्वार पर करीमनगर स्मार्ट सिटी का बोर्ड दिखता है। पता चलता है कि यह केंद्रीय परियोजना का हिस्सा है। लोग स्वीकारते भी हैं कि शहर के विकास में स्मार्ट सिटी परियोजना ने काफी योगदान दिया है। करीमनगर की राजनीति फिलहाल तो भाजपा नेता बंडी संजय के इर्द-गिर्द ही घूमती है। स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि यहां शहर के मुख्य बाजार की ओर जाने वाली सड़क के बीच में धार्मिक स्थल आ रहा था। सड़क चौडीकरण के लिए उसे हटाया जाना जरूरी था। करीब दस साल पहले बंडी संजय ने इस मामले को जोर से उठाया। उन्होंने और उनके समर्थकों ने दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल को हटाने की जोरदार पैरवी की। जानकार कहते हैं कि धार्मिक स्थल तो नहीं हटा लेकिन बंडी संजय लाइमलाइट में आ गए। तीन लाख वोटरों की वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 70 हजार मुस्लिम वोटरों की संख्या है। जीतने के बाद बीआरएस ने इन्हें साधने के लिए कई मुस्लिम संगठनों के कार्यालयों के लिए जगह दी। भाजपा ने इसे भी चुनाव में मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्वमला शीनू मुकाबले को त्रिकोणीय बनाए हुए हैं। करीमनगर जिले की हुजूराबाद सीट से भाजपा के एक और बड़े चेहरे इटाला राजेंद्र की परीक्षा है। वह बीआरएस से दो बार विधायक रह चुके हैं। बाद में भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा। बीआरएस सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी लेकिन इटाला राजेंद्र सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उन्होंने बीआरएस के गुल्लू श्रीनिवास को करीब 24 हजार वोटों से हराया था। इस बार उनके सामने बीआरएस से कौशिक रेड्डी है। रेड्डी 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़े थे, इसके बाद बीआरएस ने उन्हें एमएलसी बनाया। अब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस से युवा यू प्रणव मैदान में हैं। हुजूराबाद के ऑटो ड्राइवर बन्नी कहते हैं कि इस बार कांग्रेस का जोर है। वह भी मानते हैं कि यहां की सीट से भाजपा जीत सकती है लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के बारे में भी सुना जा रहा है। चाय की दुकान पर बैठे सादिक का मानना है कि मुस्लिम वोट यहां पर बंट रहे हैं। ज्यादा बीआरएस के साथ हैं और कुछ कांग्रेस के खाते में जाएंगे। रामपुर इलाके में मिले युवा सुधीर तो सीधा बोलते हैं कि इस सीट पर भाजपा का किसी से मुकाबला नहीं है। वह आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी में कहते हैं कि जब सौ विधायक मिलकर उपचुनाव में नहीं हरा पाए तो अब कौन सामने आएगा। वैसे तो हैदराबाद से बाहर एएमआईएम की कोई खास दस्तक नहीं हैं। लेकिन पिछले नगर पालिका चुनाव में एआईएमआईएम के सात प्रत्याशी जीते थे। एक बार डिप्टी मेयर भी रह चुका है। स्थानीय पत्रकार इन चुनावों में पार्षदों के असर को अहम मानते हैं। एक बाइक शोरूम के संचालक हबीब का कहना है कि यहां के लोग पढ़े-लिखे हैं और सोच समझकर ही वोट डालेंगे। शाकिर का कहना है कि मुस्लिम वोटर बीआरएस और कांग्रेस दोनों की ओर हैं। कांग्रेस ने अपनी छह गारंटियों में काफी कुछ दिया है। युवा रिजवान का कहना है, बीआरएस के विधायक कई बार चुने जा चुके हैं, अब बदल कर भी देखा जाना चाहिए। वह मानते हैं कि धार्मिक स्थल हटाने के मामले को बंडी संजय ने गर्माया था लेकिन एमपी बनने के बाद उन्होंने ऐसे बयानों से परहेज किया है। पिद्दापल्ली जिले में बसपा प्रत्याशी दसारी उषा ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। 27 वर्षीय उषा ने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक करने के बाद समाज सेवा का फैसला किया। युवा चेहरे को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उषा के लिए रैली को संबोधित किया। उनके सामने बीआरएस से विधायक मनोहर रेड्डी और कांग्रेस के विजय रमना राव और भाजपा से प्रदीप राव हैं।

राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी-अपनी जीत का जताया भरोसा

नीरज कुमार दुबे

राजस्थान में विधानसभा की 199 सीट पर चुनाव के लिए मतदान शनिवार सुबह सात बजे शुरू हो गया और सत्तारुढ़ कांग्रेस एवं विपक्षी भाजपा के नेताओं ने चुनाव में अपनी-अपनी जीत का विश्वास जताया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरोसा जताया है कि मतगणना के बाद ''कमल खिलेगा'' तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी वोट डालने से पहले विश्वास जताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। भाजपा नेता सतीश पूनियां ने कहा कि लोग राजस्थान में डबल इंजन सरकार बनाने के लिए वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश में जो बदलाव आना शुरू हुआ, वह जारी है और मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कि मतदाता राजस्थान में इतिहास रचने के लिए मतदान करेंगे। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी मतदान के बीच राज्य के मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने का आग्रह किया। मोदी ने पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को शुभकामनाएं भी दीं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। इस अवसर पर पहली बार वोट देने जा रहे राज्य के सभी युवा साथियों को मेरी ढेरों शुभकामनाएं।'' दूसरी ओर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और ''विकास की गारंटी'' को चुनने की अपील की। खरगे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, बचत, राहत, बढ़त और सपनों की ऊंची उड़ान, कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित जनताज चुनेगी केवल राजस्थान ! राजस्थान की जागरूक जनता को मालूम है कि उनका एक बहुमूल्य वोट उनकी खुशहाली की गारंटी है। उन्होंने कहा, महान वीरों की धरा व सामाजिक एकता के प्रतीक राजस्थान की जनता से अनुरोध है कि मतदान अवश्य करें। ये सोचें कि आपके सुधरते जीवन में कोई रुकावट न आए। हम आपको बता दें कि करणपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया है।

गहलोत के विकास और भाजपा के बदलाव में कड़ी टक्कर

अमित शर्मा

राजस्थान में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। शनिवार 25 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। मतदान शुरू होने में केवल 24 घंटे का समय शेष बचा है, लेकिन चुनाव के अंतिम क्षणों में भी अभी तक कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी। यह राजस्थान के उस मिजाज से बिल्कुल उलट है, जिसमें चुनाव के साल-छह महीने पहले ही यहां सरकार बदलने की भविष्यवाणी कर दी जाती थी। लेकिन अशोक गहलोत सरकार के विकास के कामों और जनता से किये गए वादों ने राजस्थान की यह परंपरा उलटने का काम किया है। राजस्थान चुनाव में अशोक गहलोत सरकार के विकास और भारतीय जनता पार्टी के बदलाव के बीच कड़ी टक्कर है। मामला बिल्कुल भी एक तरफ नहीं है और थोड़े-बहुत अंतर से यह किसी की भी ओर झुक सकता है। चुनाव के अंतिम क्षणों में नेता लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बाजी अपनी ओर पलटने की कोशिश कर रहे हैं।

राजधानी जयपुर से लेकर राजस्थान के बिल्कुल दूर इलाके के किसी भी गांव में जाने पर राज्य सरकार के विकास के काम दिखाई पड़ते हैं। बॉर्डर एरिया रामगढ़ में हार्डवेयर की दुकान चला रहे टीकाराम बताते हैं कि उनके यहां 12वीं तक के ही स्कूल थे। डिग्री कॉलेज दूर होने के कारण लड़कियां इससे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती थीं। लेकिन अब उनके यहां डिग्री कॉलेज और आईटीआई खुल गया है। अब लड़कियां ऊंची पढ़ाई कर रही हैं और आईटीआई पूरा करने के कारण लड़कों को नौकरी भी मिल रही है। यह सब केवल पिछले पांच सालों के अंदर हुआ है। उन्हें लगता है कि कोई भी राज्य हो इसी तरह की सरकार सत्ता में आनी चाहिए, जो लोगों के लिए काम करे और उन्हें लाभ पहुंचाये। रामगढ़ जैसी विकास की कहानी राजस्थान के हर क्षेत्र में सुनी जा सकती है।

अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख रुपये तक के इलाज की निशुल्क सुविधा देने की घोषणा कर राज्य में बड़ा दांव खेला था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा के बाद से ही इसकी सफलता पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि यदि जनता तक इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा और यह केवल घोषणा ही बनकर रह गई, तो यही योजनाएं अशोक गहलोत सरकार की अलोकप्रियता और विफलता का सबसे बड़ा कारण बनेंगी। लेकिन संभवत: राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने उसी समय यह तय कर लिया था कि उन्हें अगला चुनाव विकास और कामकाज पर लड़ना है। शायद इसीलिए योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए पूरा दमखम लगा दिया गया और उसी का परिणाम आज कांग्रेस और अशोक गहलोत को मिलता दिख रहा है।

स्थानीय लोग बताते हैं कि चिरंजीवी योजना के कारण उन्हें सरकारी और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल रहा है। जिन बीमारियों के इलाज में उनका परिवार आर्थिक तौर पर बर्बाद हो जाता था, अब बहुत आसानी से उनका इलाज करवा पा रहे हैं। गहलोत सरकार की यह योजना %गेम चेंजर% साबित हुई है। आने वाले समय में यह योजना देश की राजनीति का पैमाना भी बदल दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

इसी तरह गहलोत सरकार की महंगाई राहत योजना, आर्थिक सहायता की घोषणाओं, विभिन्न वर्गों के छात्रों के लिए जिले-जिले में हॉस्टल और महिलाओं के लिए स्मार्टफोन योजना बेहद कारगर साबित हुई है। जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का लाभ मिलने से अशोक गहलोत सरकार गरीब और कमजोर वर्गों के बीच काफी लोकप्रिय हुई है। इन योजनाओं ने कांग्रेस की चुनावी राजनीति तय करने में अहम भूमिका निभाई है। यदि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की वापसी होती है, तो उसका श्रेय इन्हीं योजनाओं को दिया जायेगा। सरकार के कामकाज से संतुष्ट स्थानीय लोग कई जगहों पर विधायकों से नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं। विधायकों की कथित मनमानी और भ्रष्टाचार से छुटकारा पाने के लिए लोग बदलाव की बात भी कर रहे हैं। राजस्थान में महिलाओं के साथ हुईं कई बड़ी आपराधिक घटनाओं ने अशोक गहलोत सरकार की छवि खराब करने का काम किया है। भाजपा ने इसे यहां बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। उनके कार्यकर्ता जगह-जगह पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि सरकार की वापसी होती है, तो इससे राज्य में अपराध बढ़ जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता राजस्थान में भी जोर-जोर से योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल का गुणगान कर रहे हैं। दागी नेताओं को पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने कथित तौर पर टिकट देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस की राज्य इकाई ने अपनी जरूरत बताते हुए ऐसे चेहरों को भी टिकट दिलवा दिया है जिनकी छवि खराब है। इससे भी अशोक गहलोत सरकार की छवि पर असर पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें ऐसी विधायकों से उन्हें छुटकारा चाहिए। यह नाराजगी विधायकों से है, सरकार के कामकाज और विकास से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कड़े मुकाबले में अंतिम परिणाम पर यह मुद्दा सरकार के कामकाज पर भारी पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के सभी बड़े नेता अपनी चुनावी सभाओं में अशोक गहलोत सरकार पर मुसलमानों का तुष्टिकरण करने के आरोप लगा रहे हैं।

चुनाव दर चुनाव भ्रष्ट आचरण की घटनाएं बढ़ रही हैं

ललित गर्ग

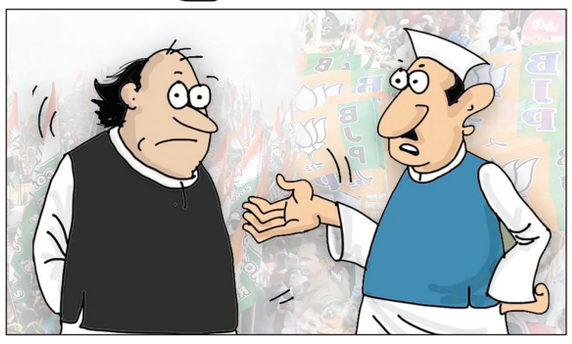

चुनाव चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के या फिर नीचे के लोकतांत्रिक संगठनों के, जहां नीति, नैतिकता एवं पवित्रता की बात पीछे छूट जाती है, वहां न केवल लोकतंत्र बल्कि राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है। तीन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और दो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। अधिक संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक कर्मियों की तैनाती भी होती है। इन प्रयत्नों एवं सतर्कताओं के बावजूद चुनावों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार एवं अनैतिकताएं सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतंत्र के सामने गंभीर संकट है। तमाम तरह की सावधानियों के बावजूद राजनैतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए नगदी, शराब, उपहार आदि का वितरण करते हुए देखे जा रहे हैं। यह बीमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हर स्तर- पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव- तक जा पहुंची है और लगातार बढ़ती भी जा रही है। यदि चुनाव को पवित्र संस्कार नहीं दिया गया तो भारत के लोकतंत्र का आदर्श धुंधला एवं दुर्बल ही होता जायेगा। जबकि निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान से ही जन प्रतिनिधियों का चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती दे पायेगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए अवैध तरीके नहीं अपनायें और मतदाता को लुभाने एवं गुमराह करने की कोशिशों से बाज आयें। जीत-हार की राजनीति में आकंठ डूबे राजनेता अब राजस्थान एवं तेलंगाना विधानसभाओं के चुनावों में लगे हैं। इसके कुछ महीनों बाद समूचा देश केन्द्र की सत्ता चुनने में लग जाएगा, लेकिन ऐसे में क्या हमारी मौजूदा दूषित होती चुनाव प्रक्रियाओं के हालातों पर विचार करना मौजूं नहीं होगा? क्या इन चुनावों के बहाने आजादी के साढ़े सात दशकों में हासिल वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा नहीं करना चाहिए?

इस माह पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, इन राज्यों में अब तक 1,760 करोड़ रुपये की नगदी, शराब, उपहार आदि की बरामदगी हुई है, चुनाव प्रक्रिया के अंत तक इसमें बढ़ोतरी का अनुमान है। मतदाताओं को रिश्वत देने, रेवड़ियां बांटने एवं लुभाने का यह चलन किस गति से बढ़ रहा है, इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इन राज्यों में इस साल बरामद नगदी और चीजों का मूल्य 2018 के चुनाव की तुलना में सात गुना से भी अधिक है। सबसे अधिक बरामदगी तेलंगाना और राजस्थान में हुई है। इन दो राज्यों में मतदान अभी होना है। मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोट डाले जा चुके हैं। राजस्थान में सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब चुनाव प्रचार के दौरान भी मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये सभी राजनीतिक दल जायज-नाजायज तरीके अपना रहे हैं। जबकि आचार संहिता के उल्लंघन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए तकनीक का भी सहारा लिया है ताकि केंद्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। बावजूद इन सख्तियों के उम्मीदवार मतदाताओं को नगदी, शराब, उपहार आदि देने के रास्ते निकाल ही रहे हैं। यहां मतदाता भी प्रलोभन में आकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। छोटे-छोटे प्रलोभनों में वे अपनी बड़ी जिम्मेदारी से मुंह फेर रहे हैं। जो जनता अपने वोटों को चंद चांदी के टुकड़ों में बेच देती हो, सम्प्रदाय एवं जाति के उन्माद में योग्य-अयोग्य की पहचान खो देती है, अपने निष्पक्ष मतदान की जिम्मेदारी को किन्हीं स्वार्थों की भेंट चढ़ा देती है, वह जनता योग्य, जिम्मेदार एवं पात्र उम्मीदवार को कैसे विधायी संस्थाओं में भेज पाएंगी? स्वस्थ एवं आदर्श लोकतंत्र की स्थापना का दायित्व जनता का ही है। वोट देते हुए वह जितनी जागरूक होगी, उतना ही देश का हित होगा।

इन पांच राज्यों- मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं तेलंगाना में हर बार की तरह इस बार भी जमकर चुनावी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। इन चुनावों में हर राजनैतिक दल अपने स्वार्थ की बात सोचता रहा तथा येन-केन-प्रकारेण ज्यादा-से-ज्यादा वोट प्राप्त करने की तरकीबें निकालता रहा। इसके लिये उसने पूर्व की अपेक्षा इस बार ज्यादा गलत, असंवैधानिक, अनैतिक एवं भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया है। जबकि आयोग पूर्व की अपेक्षा अधिक सक्रिय और सतर्क हुआ है। चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मियों में भी अधिक सचेतना देखी गयी है। लेकिन विडम्बना देखिये कि इतना सब होने के बावजूद स्वच्छ, पारदर्शी एवं शुद्ध चुनाव संभव नहीं हो पा रहे हैं। चुनावों में धन-बल का इस्तेमाल बढ़ा है, साम्प्रदायिक एवं जातीय दावपेंच बढ़े हैं। नगद धन, शराब एवं उपहार खुलेआम बांटे गये हैं। जबकि ये स्थितियां चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। इन पर नियंत्रण की प्राथमिक जिम्मेदारी और जवाबदेही आयोग की है तो राजनीतिक दलों की भी है। बढ़ता चुनावी भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या है, जिस प्रकार प्रत्याशियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की जानकारी सार्वजनिक की जाती है, उसी तरह यह भी मतदाताओं को बताया जाना चाहिए कि जो अवैध नगदी और अन्य चीजें बरामद हुई हैं, वे किस उम्मीदवार की हैं। जिस उम्मीदवार ने ऐसा दुस्साहस किया हो, उस उम्मीदवार की पात्रता को अवैध घोषित किया जाना चाहिए। चुनावी भ्रष्टाचार रोकने में मतदाताओं को भी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अनेक मतदाताओं को अपने हिताहित का ज्ञान नहीं है, इसलिये वे हित-साधक उम्मीदवार एवं दल का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अनेक मतदाता मोहमुग्ध होते हैं, इसलिये उनका मत शराब की बोतलों एवं छोटी-मोटी धनराशियों एवं स्वार्थों के पीछे लुढ़क जाता है। यह हमें समझना होगा कि जो भ्रष्टाचार के सहारे जीतेगा, वह कभी जनता की सेवा को प्राथमिकता नहीं देगा। इसलिए, चुनावी भ्रष्टाचार के रोग का उपचार आवश्यक है।

हकीकत यह भी है कि चुनाव सुधार की मांग समय-समय पर उठती रही है और खासकर उस समय जब चुनाव नजदीक आए अथवा चुनावी प्रक्रियाओं के समय चुनाव में सुधारात्मक कदम उठाने की बात ज्यादा की जाती रही है। लेकिन प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन मसलों का हल चुनाव से पहले ही क्यों नहीं निकाल लिया जाता है? इसका उत्तर यह कदापि नहीं है कि चुनाव आयोग शक्तिहीन हो चुका है। आज भी चुनाव आयोग में संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं और वह निष्पक्षता से काम भी कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो सदैव चुनाव सुधार की बात करता है, लेकिन राजनीतिक दल सदैव इसमें असहयोग और विरोध ही प्रकट करते रहे हैं। शायद यह कयास लगाना गलत नहीं होगा कि चुनाव सुधार से राजनीतिक दलों को यह भय सताता रहा होगा कि उनके मनमानी और आपराधिक संलिप्तता तथा धन का अथाह उपयोग पर रोक लग जाने से चुनावों में जीत को सुनिश्चित करना असंभव हो जायेगा। वैसे भी भारत में चुनावों में बड़ी मात्र में धन की जरूरत एक कड़वी सच्चाई है, इसके लिए निर्धारित खर्च की सीमा निरर्थक साबित होती रही है और जिसका शायद ही पालन किया जाता है।

महिलाओ के लिए ये भी हो सकते हैं बेस्ट कैरियर ऑप्शंस

कैरियर चुनने से पहले जरूरी होती हैं ये बातें जानना

पहले एक पेशा हमें अपनी ओर खींचता है मगर थोड़े ही समय बाद हमें ये ख्याल आता है कि ये हमारे बस का नहीं है। फिर हम दूसरे विकल्पों की तलाश करने लगते हैं।हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिन्हें करियर चुनते समय एक बार अपने आप से जरुर पूछना चाहिए।

हर शख्स अपने जीवन में ऐसे करियर की उम्मीद करता है, जोकि बेहतर भविष्य की गारंटी देता हो, लेकिन बेहतर भविष्य पाने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना बेहद जरूरी है। कई बार हम हमारे करियर को चुनते समय जल्दबाजी कर लेते हैं अक्सर करियर चुनने में हम गलती कर जाते हैं। पहले एक पेशा हमें अपनी ओर खींचता है मगर थोड़े ही समय बाद हमें ये ख्याल आता है कि ये हमारे बस का नहीं है। फिर हम दूसरे विकल्पों की तलाश करने लगते हैं।हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिन्हें करियर चुनते समय एक बार अपने आप से जरुर पूछना चाहिए। अगर वो करियर आपके सारे प्रश्नों पर खरा उतरता है तो आप बिलकुल सही दिशा में जा रहे हैं।

मुझे कितना पैसा मिलेगा–

नौकरी हम कमाई करने और अपना पेट पालने के लिए ही करते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी उस करियर में मिलने वाला पैसा हो जाता है। अगर उस करियर में आप मिलने वाली सैलरी से संतुष्ट हैं तभी वो करियर चुनें।

क्या मैं शादी के बाद परिवार का बोझ उठा पाउंगा–

यह अक्सर होता है जब हम बैचलर होते हैं तो बिना सोचे कोई भी करियर शुरू कर देते हैं। लेकिन बाद में वो हमारा और हमारे परिवार का खर्च उठाने के लिए नाकाफी होता है। तब फिर से करियर बदलने की नौबत आ जाती है। आपको बाद में इस समस्या से दो–चार न होने पड़े इसलिए पहले से ही इस पर सोच समझ लें।

कहीं मैं अपना करियर किसी दिखावे में तो नहीं चुन रहा हूं–

कई बार हम अपने करियर का फैसला अपने दोस्तों की देखा–देखी करते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है कि हम तो किसी दूसरी चीज में बेहतर थे। अगर आप करियर चुनने जा रहे हैं तो इस पर जरुर सोच लें।

करियर चुनते वक्त क्या आप किसी के प्रेशर में तो नहीं हैं–

करियर चुनते समय हमारे परिवार वालों की उम्मीदें हम से कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसे में हम उनके प्रेशर में करियर चुन लेते हैं लेकिन असल में हमें उस करियर में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ऐसा करियर बिलकुल न चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट न हो।

आज के समय में अपने कैरियर के प्रति जितने सचेत पुरुष रहते हैं उतनी ही सचेत महिलाये भी रहती हैं. बीते सालो की तुलना में आज के समय में वर्किंग महिलाओ की संख्या बढ़ती ही जा रही हैं. वैसे तो महिलाओ के लिए भी हर क्षेत्र में करियर बनाना आसान हैं पर कुछ ऐसे कोर्सेस और ऐसी फ़ील्ड्स हैं जो महिलाओ के लिए काफी अच्छी साबित हो सकती हैं जानिए कौन से हैं ये विकल्प :–

1) न्यूज़ रीडर

दिन पर दिन बढ़ते मीडिया ने करियर के भी अनेक अवसर खोले हैं और अब युवतियां भी मीडिया में अपना करियर बनाने में आगे बढ़ रही हैं.किसी भी न्यूज़ चैनल के लिए न्यूज़ रीडर की भूमिका अहम होती हैं और न्यूज़ रीडर के तौर और अधिकतर युवतियों को ही नियुक्त किया जाता हैं.न्यूज़ रीडर महिलाओ के लिए एक अच्छी जॉब प्रोफाइल हैं.

2) पब्लिक रिलेशन

किसी भी कंपनी की विज्ञप्ति को ब्रैंड बिल्डिंग के साथ समाचार पत्रो तक पहुँचाने का काम पब्लिक रिलेशन का होता हैं. इस क्षेत्र में महिलाओ के लिए करियर बनाने की सम्भावनाये अच्छी हैं.

3) इवेंट मैनेजमेंट

किसी ही इवेंट को ऑर्गनाइस करने का काम इवेंट मैनेजर का होता हैं और महिलाओ के लिए यह जॉब काफी अच्छी होती हैं. इवेंट मैनेजर के तौर पर आपको इवेंट के वेन्यू से लेकर मेनू तक सभी का अरेंजमेंट करना होता हैं.

4) बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आईटी

ये दोनों क्षेत्र आज के समय के सबसे ज़्यादा पसंद किये जाने वाले कोर्स हैं और इस क्षेत्र के युवाओ की खॉसी मांग भी रहती हैं. यह क्षेत्र महिलाओ के लिए भी बेहद अच्छे होते हैं जिनमे वे करियर बना सकती हैं.

5) डिजाइनिंग

डिजाइनिंग एक ऐसा कोर्स हैं जिनमे महिलाये काफी रूचि लेती हैं फैशन के लिए दौर में फैशन डिज़ाइनर्स की मांग भी बढ़ रही हैं.जोकि महिलाओ को एक सुरक्षित भविष्य भी दे सकता हैं.

सर्दी में न्यू बॉर्न बेबी की करें खास देखभाल, 5 तरीकों से ठंड में भी रखें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी

सर्दी के मौसम में बड़ों की त्वचा बेहद ड्राई, बेजान हो जाती है तो फिर सोचिए छोटे बच्चों और न्यू बॉर्न बेबी (ह्द्2 इ्श्रह्ठ ड्ढड्ढ4) का क्या हाल होगा. बच्चों की त्वचा तो बेहद नाजुक, सेंसेटिव और सॉफ्ट होती है. ठंड के मौसम में बच्चों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही बरती जाए तो वे बीमार हो जाते हैं. किसी बच्चे का जन्म ठंड के मौसम में हुआ है, तो उसे खास देखभाल की जरूरत होती है. इस मौसम में हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस काफी तेजी से बढ़ते हैं और नवजात शिशु को जल्दी अपना शिकार बनाते हैं. चूंकि, बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, ऐसे में लापरवाही बरतने से शिशु की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. चलिए जानते हैं सर्दियों में शिशु की देखभाल के लिए कौन–कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सर्दियों में शिशु की देखभाल के टिप्स

1. सर्दियों में चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे तो आप उसके शरीर के तापमान पर खास ध्यान रखें. नवजात शिशुओं को अक्सर ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया होने का खतरा रहता है. इसमें शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है. ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप शिशु को गर्म कपड़े पहनाकर रखें. उसके हाथ, पैरों और सिर को खासकर ढककर रखें.
2. बहुत ठंड में बच्चे को प्रतिदिन ना नहलाएं. हालांकि, स्नान कराने से उसकी त्वचा से गंदगी, बैक्टीरिया साफ हो सकते हैं, लेकिन एक दिन गैप करके ही स्नान कराएं. नहलाते समय सभी दरवाजे, खिड़कियों को बंद कर दें, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके. ठंडी हवा लगने से बच्चे को सर्दी–जुकाम हो सकती है.
3. सर्दियों के मौसम में बच्चों की त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई और रफ हो सकती है. ऐसे में उसके शरीर में लाल चकत्ते, खुजली, पपड़ी बनने की समस्या हो सकती है. बेहतर है कि आप प्रतिदिन बेबी स्किन केयर लोशन या मॉइश्चराइजर लगाएं. इससे त्वचा सॉफ्ट और हेल्दी रहेगी.
4. यदि आप प्रतिदिन बेबी को ठंड में स्नान कराने से डरते हैं तो साफ–सफाई का प्रॉपर ध्यान रखें. जब धूप निकल जाए तो गुनगुने पानी में कपड़ा डुबोकर पानी निचोड़ लें. इससे बच्चे के पूरे शरीर को साफ करें. फिर सूखे तौलिए से पोछ कर मॉइश्चराइजर या जैतून, सरसों का तेल लगा सकते हैं. आप मालिश करने के बाद भी बच्चे का शरीर पोछ सकते हैं. ध्यान रखें, ठंड के मौसम में हर दिन बच्चे की मालिश करें, इससे उसका बॉडी गर्म रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मांसपेशियां भी मजबूत होंगी.
5. शिशु को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो ब्रेस्टफीड कराना बेहद जरूरी है. इससे उसका प्रॉपर शारीरिक विकास भी होगा और बच्चे को भरपूर पोषण भी मिलेगा. इससे बच्चा ठंड में जल्दी बीमार भी नहीं पड़ेगा.

एग्रीकल्चर में कैरियर

कृषि से आपको लगाव है लेकिन किसी वजह से इस क्षेत्र में आने से संकोच कर रहे हैं, तो आप नए व आधुनिक तरीके से नकदी फसलों की खेती कर कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग व निर्यात करते हुए कृषि से आपको लगाव है लेकिन किसी वजह से इस क्षेत्र में आने से संकोच कर रहे हैं, तो आप नए व आधुनिक तरीके से नकदी फसलों की खेती कर कृषि उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग व निर्यात करते हुए आकर्षक मुनाफे के साथ-साथ कृषि क्षेत्र और अपने करियर को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं...

भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि केवल पारंपरिक किसानों के लिए ही है। आज के युवा भी आधुनिक तरीके से खेती करके या एग्रीकल्चर से जुड़े काम करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से ऐसी खेती करने से आत्म-सम्मान के साथ-साथ समाज में एक अलग पहचान और बेहतर मुनाफे के रास्ते भी खुले हैं। देश की काफी बड़ी आबादी आज भी कृषि क्षेत्र से ही रोजगार पाती है। कृषि क्षेत्र में मौजूद विकास की व्यापक संभावनाओं को भांपते हुए आईटीसी, मोनसेंटो और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में उतर चुकी हैं। फसलों से जुड़े शोध कार्यक्रमों में भी कृषि विशेषज्ञों की मांग तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस कृषि क्षेत्र को अपना करियर विकल्प चुनकर मिर्ती की खुशबू के साथ रहते हुए अपने करियर को सुगंधित कर सकते हैं।

प्रोडक्ट करें एक्सपोर्ट

पारंपरिक फसलों की जगह अगर नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसे आसानी से देश-विदेश में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार द्वारा इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। जरूरत है तो सिर्फ सही तरीके से उत्पादन और उसे सही बाजार तक पहुंचाने की। एक बार सही मार्केट का रास्ता मिल जाने के बाद उत्पाद हाथों-हाथ बिक जाएगा।

आकार लेतीं संभावनाएं

शोध : वैश्विक समस्या का रूप ले रहे खाद्यान्न संकट ने इस क्षेत्र को शोध संस्थाओं की प्राथमिकता का केंद्र बना दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहित देश की तमाम कृषि शोध संस्थाएं कृषि उत्पादकता बढ़ाने वाली तकनीकें और फसलों की ज्यादा उपज देने वाली प्रजातियां

फूड प्रोसेसिंग

निजी क्षेत्र की कई कंपनियां कृषि उत्पादों का ज्यादा समय तक उपभोग सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग शुरू कर चुकी हैं। डिब्बाबंद जूस, आइसक्रीम, दुग्ध उत्पाद और चिप्स जैसे उत्पाद प्रोसेस्ड फूड के उदाहरण हैं।

संगठित खुदरा बाजार

रिलायंस फ्रेश, फूड बाजार, बिग एप्पल आदि कंपनियां अपने हजारों केंद्रों के माध्यम से फल, सब्जियों, अनाज और ढेरों अन्य खाद्य वस्तुओं की बिक्री करती हैं। इसके लिए कंपनियों को थोक में खाद्य उत्पादों की खरीद करनी पड़ती है। इस कार्य में मदद के लिए ये कंपनियां कृषि विशेषज्ञों और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से जुड़े विशेषज्ञों की नियुक्ति करती हैं।

कोर्स

-बीएससी एग्रीकल्चर
-बीएससी क्रॉप फिजियोलॉजी
-एमएससी एग्रीकल्चर
-एमएससी (एग्रीकल्चर बॉटनी/ बायोलॉजिकल साइंसेज)
-एमबीए इन एग्रीबिजनेस मैनेजमेंट
-डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग
-डिप्लोमा कोर्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रैक्टिसेज

एलिजिबिलिटी

एग्रीकल्चर से संबंधित डिप्लोमा व बैचलर पाठ्यक्रम में दाखिले की न्यूनतम योग्यता विज्ञान विषयों (बायोलॉजी जरूरी) के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन के बाद एमएससी में दाखिला लिया जा सकता है। स्पेशलाइजेशन के लिए एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी आदि विकल्प मौजूद हैं। ग्रेजुएशन के बाद एग्री-बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए किया जा सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाए : भाजपा

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के चुनाव आयोग में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कथित उल्लंघन के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का आग्रह किया गया है। यह शिकायत राहुल गांधी के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर केंद्रित है। भाजपा ने आयोग से अनुरोध किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को उनके अकाउंट को तुरंत निलंबित करना चाहिए और अपमानजनक सामग्री को तत्काल प्रभाव से हटवाना चाहिए। भाजपा ने तर्क दिया कि वह पोस्ट जिसमें स्वास्थ्य सेवा, गैस सब्सिडी, कृषि ऋण राहत, अंग्रेजी शिक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित वादे शामिल थे, साथ ही राजस्थान में चल रही मतदान प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया था, जो 48 घंटे की साइलेंस जोन सीमा का उल्लंघन था। भाजपा आयोग से यह भी अनुरोध करती है कि वह राहुल के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने और आपराधिक मुकदमा शुरू करने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी राजस्थान को निर्देश जारी करे।

पीएम मोदी ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी

बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (25 नवंबर) को सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की अपनी यात्रा के दौरान बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी। प्रधानमंत्री अपनी विनिर्माण सुविधा में चल रहे काम की समीक्षा करने के लिए शहर में थे। एक सूत्र ने पहले कहा था, प्रधानमंत्री एचएएल की विनिर्माण सुविधा की समीक्षा करेंगे और दौरा करेंगे, जिसमें तेजस जेट की सुविधा भी शामिल है। मोदी रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर जोर दे रहे हैं और उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में उनके विनिर्माण और उनके निर्यात को बढ़ावा दिया है। कई देशों ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है और अमेरिकी रक्षा दिग्गज जीई एयरोस्पेस ने प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान एमके-द्वितीय-तेजस के लिए संयुक्त रूप से इंजन बनाने के लिए एचएएल के साथ एक समझौता किया था।

मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में मतदान किया

जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जोधपुर में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद उन्होंने कहा, ''राजस्थान में जो माहौल है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। राजस्थान में 'अंडरकरंट' (समर्थन की शांत लहर) चल रहा है।'' इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में 'अंडरकरंट' होने का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दावा खोखला है। गहलोत ने कहा, ''अंडरकरंट का हमारा दावा ठोस है।'' राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को दावा किया कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ कोई 'सत्ता विरोधी' लहर नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी राज्य में फिर से सरकार बनाएगी।

मुझे राजनीतिक डेंगू नहीं हुआ : अजित पवार

मुंबई। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि वह इस खबर से दुखी हैं कि वह राजनीतिक डेंगू से पीड़ित हैं और कहा कि उन्हें कोई राजनीतिक बीमारी नहीं है। उन्होंने पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं 15 दिनों से डेंगू से बीमार था। मैं इस खबर से दुखी हूं कि मुझे राजनीतिक डेंगू हो गया है। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। मुझे कोई राजनीतिक बीमारी नहीं है। मैंने अमित शाह से कोई शिकायत नहीं की। शिकायत करना मेरा स्वभाव नहीं है। राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल ने एक्स पोस्ट में कहा था कि उन अटकलें मीडिया रिपोर्टों के विपरीत, जिनमें कहा गया है कि अजित पवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग नहीं ले रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि उन्हें कल से डेंगू का पता चला है और उन्हें अगले कुछ दिनों के लिए चिकित्सा मार्गदर्शन और आराम की सलाह दी गई है। अजित पवार अपनी सार्वजनिक सेवा जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

तेलंगाना में केसीआर पर फिर बरसे राहुल गांधी

हैदराबाद। तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ चुका है। शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निज़ामाबाद में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केसीआर के परिवार के हाथ में सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्री है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब, खनन से बनाया जाता है। ये तीनों मंत्रालय केसीआर के परिवार के हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथ में नहीं होते। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि तेलंगाना में लड़ाई दोराला और प्रजाला सरकार के बीच है। आप सबने तेलंगाना का सपना देखा था और सोचा था कि यहां जनता की सरकार बनेगी, लेकिन केसीआर ने एक परिवार की सरकार बना दी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए चोरी किए। मैंने खुद जाकर देखा है कि बांध के खंभों में दरारें आ चुकी हैं। यह दोराला सरकार का सबसे बड़ा चिन्ह है।

तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री बोले- भाजपा की बनेगी सरकार

बीआरएस ने घोटालों और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया : अमित शाह

हैदराबाद। तेलंगाना में राजनीतिक दांव-पेंच लगातार जारी है। भाजपा इस दक्षिण राज्य में अपनी ताकत लगा रही है। इसकी कड़ी में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव तेलंगाना के लोगों और तेलंगाना राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव इसका मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना का गठन एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ था। उन्होंने कहा कि 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कभी राजस्व रहे तेलंगाना पर अब लाखों-करोड़ों रुपये का कर्ज है।...आज युवा निराश है। किसान, दलित और पिछड़े निराश हैं और हर कोई तेलंगाना के भविष्य को लेकर सशंकित है।

शाह ने कहा कि सभी पार्टियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद वोट करें और मेरा मानना है कि जब राज्य के मतदाता ऐसा करेंगे तो वे भाजपा को चुनेंगे। उन्होंने कहा कि इन 10 वर्षों में, बीआरएस ने भ्रष्टाचार के अलावा कोई उद्यम नहीं किया, चाहे वह मिशन भगीरथ घोटाला हो, पासपोर्ट घोटाला हो, 4000 करोड़ रुपये का मियापुर भूमि घोटाला हो, कालेश्वरम परियोजना घोटाला हो, शराब घोटाला हो, ग्रेनाइट घोटाला हो। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस कार्यकर्ता 2बीएचके आवास योजना के लिए दलितों से पैसा इकट्ठा करते हैं। तेलंगाना के लोग इन सबके बारे में जानते हैं। उनका मानना है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस ने घोटालों और भ्रष्टाचार के अलावा यहां कुछ नहीं किया।

अमित शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि तेलंगाना के जागरूक मतदाता अपना वोट डालने से पहले हर चीज़ का ठीक से विश्लेषण करेंगे और हर चीज़ की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद उनकी पसंद निश्चित रूप से कमल होगी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हम तेलंगाना में धर्म आधारित आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। हम मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को खत्म कर देंगे और इसके बजाय पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जनजातियों के लिए इसे सुनिश्चित करेंगे। हम व्यवस्था ठीक करेंगे क्योंकि तेलंगाना की जनता केसीआर की तुष्टीकरण नीति से तंग आ चुकी है।

केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अमित शाह ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया है। हैदराबाद में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा हलाल पर प्रतिबंध लगाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। शाह, जो 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, ने लोगों से पिछले दशक में चुनाव लड़ रहे दलों के प्रदर्शन को देखने के बाद वोट देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपका (तेलंगाना के लोगों का) वोट सिर्फ एक विधायक या सरकार के भाग्य का फैसला नहीं करेगा, बल्कि तेलंगाना और देश का भविष्य तय करेगा। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप प्रत्येक पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के बाद ही वोट करें। मुझे विश्वास है सोमाजीगुडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, सभी पार्टियों का विश्लेषण करने के बाद आप पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को वोट देंगे। शाह ने आगे कहा कि ये चुनाव मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं क्योंकि तेलंगाना का गठन एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ था। 10 साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि कभी राजस्व अधिशेष वाला राज्य होने के कारण अब इस पर लाखों-करोड़ों रुपये का कर्ज है।

राहुल गांधी पर बीआरएस नेता केटी रामाराव का वार

हैदराबाद। कांग्रेस तेलंगाना में अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी राज्य में लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और सत्तारूढ़ बीआरएस पर निशाना साध रहे हैं। इन सब के बीच तेलंगाना के मंत्री और बीआरएस विधायक केटी रामा राव ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज बेरोजगार हैं क्योंकि उन्होंने 2014 में अपनी नौकरी खो दी थी। उन्होंने और उनकी पार्टी दोनों ने 2014 में अपनी नौकरी खो दी थी। इसलिए आज उन्हें बेरोजगारी याद आ गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने कभी एक भी प्रवेश परीक्षा दी है? क्या उन्होंने प्राइवेट सेक्टर या किसी अन्य जगह पर एक दिन भी नौकरी की है। केटीआर ने दिवंगत पीएम पीवी नरसिम्हा राव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रियंका गांधी को दिवंगत पीएम पीवी नरसिम्हा राव के साथ हुए अन्याय के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ओर हम सभी आदर करते हैं। वह धरती के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विनम्र इंसान जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस पार्टी की सेवा की, उन्हें पार्टी द्वारा इतने अपमानजनक तरीके से अपमानित किया गया। एक मौजूदा प्रधान मंत्री के रूप में, उन्हें 1996 में संसद सदस्य बनने के लिए पार्टी टिकट से वंचित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैं प्रियंका गांधी को यह भी याद दिला दूं कि उनके निधन के बाद, एआईसीसी प्रमुख ने उनके शरीर को 24 अकबर रोड कार्यालय पर लाने की भी अनुमति नहीं दी थी।

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज

पोस्टर पर किसकी फोटो बड़ी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता : पायलट

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने विश्वास जताया कि पार्टी राज्य में फिर से सत्ता में आएगी और कहा कि भाजपा पिछले पांच वर्षों में विपक्षी दल के रूप में गायब थी। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस मौजूदा राजस्थान विधानसभा चुनाव एक एकजुट ताकत के रूप में लड़ रही है और उम्मीद जताई कि लोग पार्टी को फिर से वोट देंगे और हर पांच साल में एक मौजूदा पार्टी को सत्ता से बाहर करने की प्रवृत्ति को खत्म करेंगे। मीडिया के साथ एक विशेष साक्षात्कार में पायलट ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी क्योंकि उसने समयबद्ध तरीके से युवाओं सहित लोगों के मुद्दों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा पिछले पांच वर्षों से राज्य में विपक्षी दल के रूप में गायब थी।

उन्होंने कहा हमने पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर प्रचार किया है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ऊर्जावान हैं। राजस्थान में नेतृत्व विभाजित है। उनके बीच अंदरूनी कलह है। मेरा मानना है कि लोग रिवाज़ (सरकार बदलने की परंपरा) को बदल देंगे। हम सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि 2013 और 2018 के बीच की अवधि कांग्रेस के लिए एक कठिन अवधि थी जब वह विपक्ष में बैठी थी और भाजपा राजस्थान में सरकार का नेतृत्व कर रही थी। पायलट ने कहा तब हमारे पास 21 विधायक थे। यह हमारे लिए एक कठिन दौर था। हमने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए धरना, विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल की, लाठीचार्ज का सामना किया और जेल गए। हम उनकी आवाज़ थे। लेकिन अब, हम हैं। हमने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए। इसलिए, हम और अधिक ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी पांच साल तक विधानसभा और सड़कों से विपक्ष के रूप में गायब रही। उनके पास (2013 में) 163 विधायक थे और उनके पास लोगों की आवाज बनने का मौका था। अब, वे रथ यात्रा और जन आक्रोश यात्रा कर रहे हैं और ये बहुत अधिक कर्षण नहीं मिल रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, पायलट ने कहा कि ऐसे बयान तथ्यात्मक रूप से गलत थे और 2014 के बाद से केंद्र में भाजपा द्वारा किए गए कार्यों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए दिए गए थे। पायलट ने कहा पीएम मोदी ने मेरे परिवार के बारे में कहकर अपने शब्दों को सच्चाई से परे रखा। यह लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या किया? क्या आपने राजस्थान के लिए किसी परियोजना, पहल या विभिन्न पैकेज की घोषणा की?

उन्होंने पीएम मोदी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, लोग जानते हैं कि किसने क्या काम किया है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी पोस्टर पर आपकी तस्वीर सबसे बड़ी हो। कांग्रेस नेता ने कहा, लोग अब आश्वस्त हैं कि भाजपा एकजुट नहीं है, लेकिन कांग्रेस एकजुट है और एक टीम के रूप में और पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। यह पूछे जाने पर कि यदि कांग्रेस राजस्थान चुनाव बहुमत से जीतती है तो क्या वह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पायलट ने इस तरह का निर्णय लेने का फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। 200 सदस्यीय राजस्थान विधानसभा के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच आज

नईदिल्ली। पहले मैच में औसत प्रदर्शन करने वाले भारत के युवा गेंदबाज आस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को दूसरे टी20 मैच में अपनी गलतियों से सबक लेकर बेहतर प्रदर्शन के इरादे से उतरेंगे। भारत ने विशाखापत्तनम में पहला मैच दो विकेट से जीतकर पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 से बढत बना ली थी।

तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को छोड़कर हालांकि बाकी भारतीय गेंदबाज आस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा सके। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच और हालात बहुत अलग नहीं होंगे लिहाजा भारतीय गेंदबाजों को एक इकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। पहले मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा ने क्रमश: 10 . 25 और 12 .50 की औसत से रन दिये जबकि स्पिनर रवि बिश्नोई ने 13 .50 प्रति ओवर की औसत से रन दे डाले। टी20 प्रारूप में गेंदबाजों के लिये बहुत कुछ नहीं होता लेकिन इन तीनों की गेंदबाजी में विविधता का अभाव दिखा। भारत को श्रृंखला में बढत बनानी है तो इन तीनों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। यह असंभव भी नहीं है क्योंकि मुकेश ने विविधता के साथ ऐसा कर दिखाया है। दूसरे गेंदबाजों को भी उनके नक्शेकदम पर चलना होगा। लंबे समय बाद शीर्ष स्तर पर खेलने का कारण दिया जा सकता है लेकिन आजकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कार्यक्रम ऐसा है कि खिलाड़ी को सदैव सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये तैयार रहना होता है। बिश्नोई को समझना होगा कि वह सिर्फ गुगली पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि बल्लेबाज उन्हें भांप लेते हैं। उन्हें इसमें बदलाव करना होगा। हाल ही में वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे प्रसिद्ध ने नेट पर शीर्ष खिलाड़ियों को देखा है लेकिन उनकी गेंदबाजी में कुछ नयापन नजर नहीं आया। बल्लेबाजी में कप्तान सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन, रिंकू सिंह और यशस्वी जायसवाल ने अच्छा प्रदर्शन किया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

केंद्र ने सर्ट-इन को आरटीआई अधिनियम के दायरे से दी छूट

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे से छूट दे दी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला सर्ट-इन कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसे साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय करने के अलावा उनकी रोकथाम के लिए दिशानिर्देश और सलाह जारी करने का भी काम सौंपा गया है। कार्मिक मंत्रालय की 23 नवंबर की एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, मंत्रालय ने आरटीआई अधिनियम की धारा 24 में संशोधन किया है और सर्ट-इन को पारदर्शिता कानून के दायरे से छूट प्राप्त संगठनों की सूची में सर्ट-इन को 27वें स्थान पर रखा गया है।

बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में 2.46 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची

नईदिल्ली। जाने-माने निवेशक वॉरेन बफे समर्थित बर्कशायर हैथवे ने शुक्रवार को खुले बाजार में सौदों के जरिए पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में अपनी पूरी 2.46 प्रतिशत हिस्सेदारी 1,371 करोड़ रुपये में बेच दी। बर्कशायर हैथवे इंक ने अपने सहयोगी बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स के माध्यम से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर पेटीएम के 1.56 करोड़ से अधिक शेयर बेचे। एनएसई पर उपलब्ध थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार बीएच इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने 1,56,23,529 शेयर बेचे, जो पेटीएम में 2.46 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। सौदों का निपटान औसतन 877.29 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया गया, जिससे लेनदेन का मूल्य 1,370.63 करोड़ रुपये रहा।

आरबीआई ने बीओबी समेत कई बैंकों पर लगाया जुर्माना

नईदिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवर सीज बैंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आरबीआई ने इन बैंकों के खिलाफ जुर्माना लगाया है, क्योंकि ये बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इन बैंकों पर आरबीआई ने भारी जुर्माना लगाया है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने सख्त कार्रवाई करते हुए सहकारी बैंक के बोर्ड को भी भंग कर दिया है। इसकी कमान अब रिजर्व बैंक के हाथ में आ गई है। पांच अन्य को ऑपरेटिव बैंकों पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है। इन सभी बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 10.34 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना सिटीबैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर लगा है। तीनों बैंकों में सर्वाधिक जुर्माना सिटी बैंक पर लगा है।जानकारी के मुताबिक सिटी बैंट पर पांच करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपये और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रौद्योगिकी का सुरक्षा, विश्वास के नजरिये से नियमन जरूरी

नयी दिल्ली। सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि सुरक्षा और विश्वास के नजरिये से इंटरनेट और प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक नियमन नहीं होने पर यह उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने कहा कि नवाचार का अत्यधिक नियमन न करते हुए सुरक्षा ढांचे को सावधानीपूर्वक विकसित किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने यहां आयोजित डेट विद टेक कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) हाल के समय की सबसे बड़ी खोज में से एक है और सरकार डिजिटल मंचों पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लगभग 85 करोड़ भारतीय पहले से ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और वित्त वर्ष 2025-26 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.2 अरब हो जाने का अनुमान है।

विश्व कप हारने के बाद सराहना-आलोचना के बाद राजनीति तेज!

अमिताभ श्रीवास्तव

पचास ओवर के एकदिवसीय मुकाबलों के विश्व कप को हारने के बाद सराहना-आलोचना के बाद राजनीति भी चरम पर है। कहा यह जाता है कि खेलों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। मगर बेफिक्र बयानबाजी क्रिकेट की आड़ में अपने हितों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

कोई इस बात पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है कि वर्ष 1987 में कोलकाता में हुआ पहले विश्व कप का अंतिम मुकाबला वर्ष 2011 में मुंबई से वर्ष 2023 में अहमदाबाद कैसे पहुंच गया। हालांकि इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि विश्व कप जैसे अंतरराष्ट्रीय मुकाबले चंद दिनों की तैयारी से नहीं होते हैं। उनके पीछे साल-महीने की कोशिश होती है। यह तो किसी को मालूम ही नहीं होता कि आखिरी दौर में कौन पहुंचेगा। अवश्य ही आयोजन से संबंधित निर्णय राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर विचार कर लिए जाते हैं। उस दौरान कानून और व्यवस्था के सवाल पर भी जवाब मांगा जाता है। विश्व कप-2023 में कोलकाता में एक सेमीफाइनल और मुंबई में दूसरे सेमीफाइनल का आयोजन दोनों राज्य सरकारों के मंथन का विषय है। दोनों ही स्थान कभी क्रिकेट की राजनीति से लेकर क्रिकेट के मुख्य केंद्र के रूप में पहचान रखते थे। आश्चर्यजनक रूप से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यह दावा करने से चूक नहीं रहीं कि विश्व कप का फाइनल मुकाबला यदि कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होता तो भारत जीत जाता।

वहीं ऐसी ही बात शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राऊत भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि फाइनल का मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो भारत जीत

जाता। हालांकि वर्ष 1987 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ हुए फाइनल मुकाबले में पहली बार ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता बना था। इसके बाद दूसरी बार विश्व कप का फाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। इन दोनों सालों के बीच भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से विश्व कप का आयोजन किया, जिनमें न तो भारत फाइनल में पहुंचा और न ही फाइनल मुकाबला भारत में हो पाया।

स्पष्ट है कि खेल के बहाने राजनीति तो की जा सकती है, लेकिन उसके आयोजन और खेल प्रदर्शन की सच्चाई पर भ्रम फैलाना आसान नहीं होता है। विश्व कप के बहाने ध्यान देने योग्य बात यह है कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र दोनों गाहे बगाहे अपनी आर्थिक प्रगति की राह में आने वाली बाधाओं को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के बाद लंबे समय से एक पार्टी की सरकार है।

किंतु वहां व्यापार-उद्योग के सहायक तत्व कम और कमजोर हो रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता से लेकर कई दलों की सरकारें और उनका अपनी-अपनी दिशा में भागना राज्य में घटते निवेश का बड़ा कारण बन रहा है। राज्य में लंबे समय से अनेक उद्योगों के गुजरात चले जाने का रोना रोया जा रहा है। लेकिन अनेक उद्योग दक्षिण भारत के राज्यों ने बुला लिए हैं। कुछ उद्योग उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की ओर जाने लगे हैं। निवेश के नाम पर कई सरकारों के दावों के बावजूद राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में कोई बड़ा अंतर नजर नहीं आता है। बेरोजगारी और गरीबी से निपटना अभी-भी संकट बना हुआ है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के बीच राज्य की बेरोजगारी तीन से चार फीसदी के बीच रही है। बरसात की बेरुखी से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। इसके बीच उद्योगों का भी सहारा नहीं रहा तो किस तरह से स्थितियां सुधरेंगी। महाराष्ट्र में पर्यटन के क्षेत्र में भी अनेक अवसर उपलब्ध हैं, किंतु उनके लिए भी सहायक अवसरों की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अनेक स्थानों पर पानी की दिक्कत और लगातार हो रहे आंदोलन निवेशकों की खासी चिंता का कारण हैं। मगर राज्य सरकार के केवल दावे ही दावे सुनाई दे रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में कयासों का बाजार गर्म

विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर छत्तीसगढ़ में कयासों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है राज्य में कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो किसी का मत भाजपा के पक्ष में हैं। भाजपा और कांग्रेस अपने-अपने स्तर पर चुनाव नतीजों की समीक्षा में लगे हैं। जमीनी हकीकत को लेकर प्रत्याशियों से फीड बैक भी ले रहे हैं और उनकी शिकवा-शिकायत भी सुन रहे हैं। शिकायतों के आधार पर कांग्रेस ने कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल भी दिया। सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल ताल ठोंक रहे हैं, पर संख्या बल को लेकर दोनों दल सशंकित बताए जाते हैं। बागियों और अधिकृत प्रत्याशियों के लिए काम न करने को लेकर दोनों दलों में एक जैसा सुर ही है। कहते हैं एक विधानसभा में भाजपा के चुनाव संचालक ने खर्चे के लिए राशि नहीं मिलने पर चुनाव दफ्तर ही बंद कर चले गए। पैसे आने के बाद ही दफ्तर खोला। खबर है कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता और मंत्री भी शिकवा-शिकायत के लिए प्रभारी महासचिव सैलजा के पास पहुंच गए। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गजों की हालत भी पतली है, ऐसा न होता तो शिकवा-शिकायत की नौबत ही नहीं आती। पिक्चर तो तीन दिसंबर को ही साफ़ होगी।

इस्टीमेट देख भाजपा प्रत्याशी के उड़े होश

कहते हैं रायपुर संभाग के एक भाजपा प्रत्याशी को चुनाव संचालक और विधानसभा के संयोजक ने साढ़े बारह करोड़ का इस्टीमेट थमा दिया। चर्चा है कि दोनों पदाधिकारियों ने प्रत्याशी के सामने शर्त रख दी कि साढ़े बारह करोड़ उनके पास जमा करेंगे तो ही वे काम कर पाएंगे।

रवि भोई

पदाधिकारियों ने कहा इस सीट में 10 करोड़ खर्च होता ही है। प्रत्याशी ने उनकी शर्त सुनकर हाथ जोड़ लिए और राशि देने में असमर्थता जताई। इस पर दोनों पदाधिकारी नाराज हो गए और यहाँ तक कह दिया कि जब पैसा नहीं था तो पार्टी की टिकट क्यों ली?प्रत्याशी ने पदाधिकारियों को पैसे देने की जगह अपनी टीम बना ली और जैसे-तैसे चुनाव प्रबंधन किया । इस प्रत्याशी को किस्मत का धनी माना जा रहा है। सालों बाद प्रत्याशी की किस्मत चमकी और पार्टी की टिकट मिल गई। अब सबको नतीजे का इंतजार है।

चुनावी दंगल में फंसे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे

कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल के बेटे अमितेश शुक्ल और पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा के बेटे अरुण वोरा इस बार चुनावी दंगल में फंस गए हैं। दोनों के खिलाफ भाजपा ने नए चेहरे मैदान में उतारे हैं। चर्चा है कि एंटी इंकम्बैंसी फैक्टर और भितरघातियों के फेर में दोनों उलझ गए हैं। 2018 में अमितेश शुक्ल राजिम से ही 58 हजार से अधिक वोटों से जीते थे। अरुण वोरा ने भी दुर्ग से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 21 हजार से अधिक मतों से हराया था। गौरतलब है कि दोनों के पिता संयुक्त मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी भी पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं। दो धाकड़ लोगों की लड़ाई में अमित जोगी कितना वोट हासिल कर सकते हैं, इसी की चर्चा है।

राजेंद्र कटारा को क्लीन चिट?

बीजापुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा को लेकर भाजपा लगातार शिकायत कर रही है। भाजपा उन पर पक्षपात का आरोप लगा रही है। कहते हैं भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने करीब पखवाड़ेभर पहले जांच रिपोर्ट बुलवाई थी। कहा जा रहा है जांच रिपोर्ट में राजेंद्र कटारा के खिलाफ शिकायत सही नहीं पाई गई। भाजपा की टीम शुक्रवार को फिर राजेंद्र कटारा की शिकायत लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दफ्तर गई और उन्हें मतगणना कार्य से दूर रखने की मांग की। खबर है कि भाजपा की टीम को सीईओ ने बीजापुर कलेक्टर के खिलाफ शिकायत सही नहीं पाए जाने की जानकारी दे दी। बीजापुर में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भाजपा प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी से है। विक्रम मंडावी अभी विधायक हैं। बीजापुर विधानसभा में सात नवंबर को मतदान हुआ था।

पोस्टिंग के इंतजार में अफसर

2001 बैच की आईएएस अफसर शहला निगार और 2005 बैच की आईएएस अफसर आर. शंगीता छुट्टी से लौट आई हैं और अब पोस्टिंग के इंतजार में हैं। 2011 बैच के आईएएस अफसर संजीव कुमार झा और 2012 बैच के आईएएस अफसर तारण प्रकाश सिन्हा की पोस्टिंग भी अभी तक किसी विभाग में नहीं हुई है। इन दोनों अफसरों को अक्टूबर में चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार ने कलेक्टर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। संजीव झा बिलासपुर के और तारण सिन्हा रायगढ़ के कलेक्टर थे। कहते हैं विधानसभा चुनाव के कारण सरकार में रुटीन फाइल भी नहीं चल रही है, इस कारण आईएएस अफसरों की पोस्टिंग भी अटकी है।

कांग्रेस नेता की धर्मगुरु से डील की चर्चा

कहते हैं एक कांग्रेस नेता को अपनी जीत के लिए एक धर्मगुरु से लंबी डील करनी पड़ी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता को अपनी हार का अहसास होने के बाद धर्मगुरु की शरण में जाना पड़ा। कांग्रेस नेता कई बार से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस नेता जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां एक विशेष धर्म के वोटर काफी संख्या में हैं और वही हार -जीत का फैसला करते हैं। खबर है कि धर्मगुरु से डील के बाद समाज में प्रभाव रखने वाले करीब 40-50 लोग कांग्रेस नेता के समर्थन में उतरे। बताते हैं प्रारंभिक चरण में कांग्रेस नेता के खिलाफ बदलाव की हवा चल पड़ी थी। धर्मगुरु की कृपा से माहौल बदला।

हार-जीत का अंतर कम रहने के कयास

इस बार के विधानसभा चुनाव में कयास लगाया जा रहा है कि हार-जीत का अंतर काफी कम रहने वाला है। विश्लेषक और राजनीतिज्ञ मानकर चल रहे हैं कि सभी सीटों में मुकाबला कांटे का रहा। इस कारण प्रत्याशियों की जीत -हार काफी कम वोटों से होगी। जानकारों को किसी भी सीट में एकतरफा मुकाबला नजर नहीं आ रहा है। 2018 में मोहम्मद अकबर कवर्धा से 59 हजार से अधिक मतों से जीते थे। माना जा रहा है कि इस बार किसी भी प्रत्याशी के जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं होगा।

'आप' चर्चा से गायब

विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) बड़ी चर्चा में थी, लेकिन चुनाव के दौरान वह सुर्खियों में नहीं रही। मतदान के बाद भी लोग 'आप' को याद नहीं कर रहे हैं। बसपा और जोगी कांग्रेस के कुछ सीटों पर जीत की बात हो रही है, लेकिन आप की जीत की बात कोई नहीं कर रहा है। नतीजों के बाद कांग्रेस और भाजपा को बहुमत नहीं मिलने पर बसपा और जोगी कांग्रेस की भूमिका की भी बात हो रही है।

संविधान हमे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता से जीने के अधिकार प्रदान करता है: न्यायमूर्ति राजेंद्र चंद्र सिंह

रायपुर। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया, आयोजन का विषय आदिवासियों के सामाजिक-कानूनी मुद्दे रहा। इस उपलक्ष में विश्वविद्यालय के विधि विभाग और राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र विभाग द्वारा वाद-विवाद प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और फूड स्टॉल का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगित में प्रतिभागियों एवं विजेताओ को मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के आरंभ में विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री हर्ष गौतम ने स्वागत उद्बोधन देते हुए सभी को भारत के संविधान कि प्रश्तावना की शपथ दिलाई और कुलसचिव डॉ सौरभ के. शर्मा ने अपने शब्दों में विद्यार्थियों को संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.के. सिंह ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनायें दी।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ,मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत पूर्व न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अपने शब्दों में कहा की संविधान में दिए गए दायित्वों को देश के सभी नागरिकों को हमेश निभाना चाहिए और संविधान हमे व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता से जीने के अधिकार प्रदान कर यह भी सुनिश्चित करता है की हमारे देश का शाशन और प्रशासन किसे चले। संविधान हमे अधिकार के साथ दायित्व भी देता है जिन्हें हमे कभी भी नहीं भूलना चाहिए।

सिंधी काउंसिल ने किया नगर कीर्तन का स्वागत

रायपुर। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा आज गुरु पर्व के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया. जिसका स्वागत सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई ने तेलघानी नाका चौक में किया.

जिसमें प्रसाद का वितरण किया गया साथ में पंच प्यारो को माला पहनाकर एवम गुरु से मथा टेक कर आशीर्वाद लिया इस अवसर पर सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ,सिंधी एकेडमी अध्यक्ष राम गिडलानी,सचिन मेघानी,युवा अध्यक्ष रवि ग्वालानी,जीतेंद्र मलघानी,राजेश पोपटानी,कमल लहेजा,संजय जैसिंघ,गौतम रेलवानी,महेश खिलनानी, मोनू आहूजा,आशीष वासवानी,चंदन जैसिंघ एवम अन्य उपस्थित थे.

ईवीएम की सुरक्षा में लगे हैं 200 से ज्यादा जवान, 32 सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही नजर

मतगणना के दिन 500 से अधिक जवान रहेंगे तैनात

रायपुर। राजधानी रायपुर के सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कालेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें तीन लेयर की सुरक्षा में रखी गई हैं। यहां तीन एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। सबसे पहले सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और जिला पुलिस के जवान हैं। कुल 200 जवान तैनात हैं। इसके अलावा 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां 24 घंटे लाइव दिखाया जा रहा हैं। जानकारी के अनुसार जवानों को ड्यूटी शिफ्ट में हैं। यहां जवानों के साथ फायर सेफ्टी, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम में रायपुर जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों ईवीएम मशीन जमा हैं। इनमें रायपुर दक्षिण, रायपुर उत्तर, रायपुर पश्चिम, रायपुर ग्रामीण के अलावा आरंग, अभनपुर और धरसींवा विधानसभा क्षेत्र से ईवीएम मशीनें हैं। अब इन्हीं ईवीएम मशीनों से तीन दिसंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होंगे। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा ऐसी है कि कालेज परिसर में जैसे कोई प्रवेश करता है तो जवानों की नजर उसकी तरफ बढ़ जाती है। फिर स्ट्रांग रूम के पास रजिस्ट्रार में नाम वगैरह आदि लिखना पड़ेगा। सुरक्षा को देखते हुए कई बड़े अधिकारियों की टीम 24 घंटे में किसी भी वक्त पहुंचकर जायजा भी ले रहे हैं, ताकि सुरक्षा में किसी तरह के कमी न रह जाए।

मतगणना तीन दिसंबर को होगी। 500 से अधिक जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी हैं। पार्किंग समेत सड़कों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाएगा। इसके अलावा सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होंगे

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

प्रिंसिपल ऑफ द ईयर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होंगे संजय कुमार पांडेय

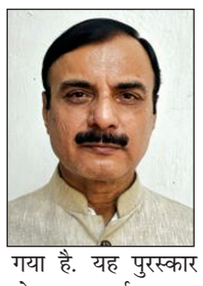

बलौदाबाजार. अंबुजा विद्यापीठ के प्राचार्य संजय कुमार पांडेय का चयन यूनिवर्सल मेंटोर एसोसिएशन द्वारा प्रिंसिपल ऑफ़ द ईयर 2023 के लिए किया गया है. यह पुरस्कार 1 दिसम्बर, 2023 को होटल क्लार्क, जयपुर (राजस्थान) में प्रदान किया जाएगा. यह पुरस्कार शैक्षणिक उत्कृष्टता और गुणवत्तापूर्ण प्रकाशन के लिये प्रदान किया जाता है. संजय कुमार पांडेय शिक्षा में नवाचार के पक्षधर हैं. उनका पूर्ण विश्वास है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए स्मार्ट लर्निंग त्रिभुज का पूर्ण होना आवश्यक है. साथ ही बच्चों की 3 से 8 वर्ष की आयु उनके सीखने का स्वर्णिम काल होता है. इन सभी का विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पैरेंटिंग-लर्निंग एण्ड अनलर्निंग (भाग-1) में किया है. विदित हो कि पूर्व में भी प्राचार्य पांडेय को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, रास्ट्रीय विद्या सरस्वती पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, शिक्षक रत्न पुरस्कार, अवंतिका राष्ट्रीय सेवा सम्मान, शिक्षाविद पुरस्कार, अवंतिका डॉ. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, बेस्ट परफ़ॉरमिंग प्रिंसिपल- अम्बुजा विद्या निकेतन ट्रस्ट, अवंतिका- आचार्य शिरोमणि पुरस्कार प्राप्त हो चुका है.

आर्टिफिशियल ज्वेलरी शाप में चोरी करने वाला पकड़ाया

रायपुर। राजधानी के जयराम कॉम्पलेक्स स्थित पदमावती ज्वेलरी शॉप में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है. वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है.

प्रार्थी भावेश जैन ने थाना मौदहापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि जयराम कॉम्पलेक्स में पदमावती ज्वेलरी (इम्युटेशन ज्वेलरी) के नाम से दुकान संचालित करता है. 9 नवंबर को रात्रि अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर घर चला गया था, 10 नवंबर को सुबह दुकान खोलने पर पूरा सामान बिखरा मिला. सामान चेक करने पर पाया कि गल्ले में रखा नगदी रकम एवं दुकान में रखा इम्युटेशन ज्वेलरी और मोबाइल फोन नहीं था.

अज्ञात चोर ने दुकान के विन्डो एसी का ग्रील काटकर दुकान अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी को अंजाम दिया था. प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 256/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया. मामले की जांच में जुटी पुलिस टीम को आरोपी भाठागांव, टिकरापारा निवासी राधेश्याम नाग की जानकारी मिली, जिसे पकड़कर पूछताछ की गई. आरोपी राधेश्याम नाग ने अपने साथी अम्बिकापुर निवासी अकरम अंसारी के साथ मिलकर चोरी को अंजाम देना स्वीकार किया. आरोपी राधेश्याम नाग को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लगभग 30,000 रुपए कीमत की आर्टिफिशियल ज्वेलरी जब्त किया गया. प्रकरण में फरार आरोपी अकरम अंसारी की पतासाजी की जा रही है.

बांग्लादेश से आकर राजधानी में की 21 लाख की चोरी, दो महिला गिरफ्तार

रायपुर। माना थाना क्षेत्र के सिद्धी विनायक कालोनी स्थित सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की दो महिला आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपित फरार है। पुलिस उनकी तलाश में है। फरार आरोपित मूलत: बांग्लादेश के रहने वाले हैं। आरोपित अबु तालेब, असलम शेख फरार है। इनकी पत्नी फातिमा बीबी और यास्मीन बीबी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित माना क्षेत्र में किराए के मकान में रूके थे। मौका देखकर चोरी की वारदात की। और यहां से फरार हो गए। महिला आरोपितों को पश्चिम बंगाल के जिला दक्षिण 24 परगना स्थित ग्राम बांसरा से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चोरी की नकदी रकम तीन खाल 50 हजार और चांदी की दो जोड़ी पायल, ट्राली बैग और घटना में प्रयुक्त दो नग मोबाइल फोन जब्त किया गया है। फरार आरोपित सोने-चांदी के जेवर और नकदी अपने पास रखे हैं। प्रार्थी सुरेन्द्र साहू ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वे सिद्धी विनायक कालोनी माना कैंप में रहता है। जमीन खरीदी-बिक्री का काम करता है।17 नवंबर को वह घर में ताला लगाकर अपनी पत्नि व पुत्री के साथ घुमने गया था। शाम को वापस घर आकर देखे तो बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। बेडरूम के खिड़की का राड भी टूटा हुआ था।

रायपुर से चुराए लाखों के गहने और नकदी, ओडिशा में गलवाया

रायपुर। सूने मकान का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपये की चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्यों सहित 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आये हैं। आरोपियों ने शैलेन्द्र नगर स्थित सूने मकान को अपना निशाना बनाया था। घटना में संलिप्त आरोपी सुनील सोना उर्फ बिलवा, सूरज सोना और पूनम सोना मूलत: ओडिशा के निवासी हैं। आरोपी सुनील सोना उर्फ बिलवा है शातिर चोर जो पूर्व में नकबजनी के कई मामलों में रायपुर के अलग अलग थानों से जेल निरूद्ध रह चुका है। प्रकरण में संलिप्त आरोपी सुनील सोना उर्फ बिलवा, संजय चौहान तथा मोहन सराफ फरार हैं। मामला कोतवाली थाना का है। दरअसल शैलेन्द्र नगर निवासी नरेन्द्र कुमार जैन ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 नवंबर को शाम 4 बजे वह अपने परिवार के साथ घर में ताला लगाकर पिकनिक के लिये रायपुर से बाहर गया था। 16 नवंबर की रात्रि करीबन 2 बजे जब वे वापस पहुंचे तो देखा की उसके घर का ताला टूटा हुआ था। अंदर देखा अलमारी का ताला टूटा हुआ था और उसमे रखे सोने चांदी के जेवरात और नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर का ताला तोड़कर घर अंदर प्रवेश कर अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 452/23 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिसकी जांच पड़ताल के दौरान सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों के देखने पर टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई।

अधिकारियों की मनमानी से लक्ष्य से दूर हो रहा ओपन स्कूल

रायपुर। शिक्षा के अधिकार के तहत बनाया गया ओपन स्कूल अधिनियम छत्तीसगढ़ में उद्देश्यों से भटकता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों की मनमानी और बच्चों को नहीं समझने के अहंकार के चलते सभी को शिक्षित करने शासन का उद्देश्य असफलता की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले कई सालों से ओपन स्कूल में बैठने वाले छात्रों की संख्या में असफल होने वाले कही ज्यादा है। इसे लेकर विभागीय अधिकारियों का अलग ही तर्क है। वे कहते हैं कि इसमें फेलवर या पढ़ाई छोड़ चुके बच्चे ही बैठते हैं, कहकर अपनी कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर हकीकत यह है कि कठिन पाठ्यक्रम, कठिन प्रश्न पत्र और कड़ाई से परीक्षा लेने होने की वजह से ज्यादातर विद्यार्थी इसमें असफल हो रहे हैं। ओपन स्कूल में बैठने वाले छात्रों से सख्त रुख अपनाए जाने से सबसे ज्यादा परेशान अभिभावक होते है जिन्हें दोहरी मार पड़ी है। साल बरबाद न हो इसकी उम्मीद लिए पालकों के मेहनत का पैसा बच्चों का भविष्य बनाने अलग बरबाद होता है साथ ही कीमती शैक्षणिक वर्ष भी चला जाता है। जानबूझकर अफसर इस स्तर का पेपर सेट करते हैं जैसे सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा हो। प्रदेश में अगले कुछ दिनों में नई सरकार शपथ ले लेगी। पालकों को इस बात की उम्मीद है कि नए शिक्षा मंत्री इस बात की संज्ञान लेंगे और अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाएंगे ताकि विद्यार्थी बगैर कठिनाई कम से कम स्कूली शिक्षा तो पूरी कर सकेंगे।

अग्रसेन महाविद्यालय में मनाया गया संविधान दिवस?

भारतीय संविधान से ही यहाँ लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं

रायपुर. अग्रसेन महाविद्यालय में आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इसमें शासकीय जे. योगनान्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में विधि विभाग के प्राध्यापक डॉ भूपेन्द्र करवंदे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे. अपने संबोधन में उन्होंने कहा भारत का संविधान पूरे विश्व में अपनी समग्रता और विशिष्टता के कारण एक अलग स्थान रखता है. इसमें हर एक नागरिक के समस्त अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. इसी वजह से भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं. डॉ करवंदे ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का न केवल सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, बल्कि यह सबसे विशिष्ट भी है. क्योंकि इसमें मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार और मानव अधिकारों को भी शामिल किया गया है. उन्होंने अलग-अलग उदाहरणों से विद्यार्थियों को संविधान की विभिन्न विशेषताओं से भी परिचित कराया. कार्यक्रम के आरंभ में महाविद्यालय के छात्रों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की. इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष तथा

महाविद्यालय के डायरेक्टर डॉ वी.के. अग्रवाल ने कहा कि संविधान निर्माता डॉ भीमराव आंबेडकर सहित संविधान सभा के समस्त सदस्यों के सम्मिलित प्रयासों से इसमें अधिकारों के साथ ही कर्तव्य को समान महत्व दिया गया है, ताकि देश का हर व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बन सके . महाराजाधिराज अग्रसेन शिक्षण समिति के अध्यक्ष तथा महाविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटर डॉ. अमित अग्रवाल ने संविधान दिवस के इस कार्यक्रम को युवाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी बताया.

आभार प्रदर्शन करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ युलेन्द्र कुमार राजपूत ने कहा कि संविधान ही भारतीय शासन व्यवस्था की आत्मा है, और इसके माध्यम से हर एक नागरिक के लिए न्याय को सुनिश्चित किया गया है. कार्यक्रम का संयोजन पत्रकारिता संकाय की विभागाध्यक्ष डॉ अदिति नामदेव गुप्ता ने किया तथा इसका संचालन पत्रकारिता संकाय के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. विभाष कुमार झा ने किया. कार्यक्रम में महाविद्यालय के विद्यार्थियों तथा सभी संकायों के प्राध्यापकों ने पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की.

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को डी. लिट की उपाधि

रायपुर। कलिंगा इंस्टिट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेस, भुवनेश्वर द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन को आज आयोजित संस्थान के दीक्षांत समारोह में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों एवं समाज में उनके महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में, डी. लिट. (डिग्री ऑफ़ लेटर्स) की मानद उपाधि प्रदान की गई।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.